राष्ट्रीय

छात्रशक्ति

वर्ष-48 ■ अंक-04 ■ सितम्बर 2026 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-40



उत्तराखंड से केरल तक

लहराया भगवा

अभाविप दक्षिण बिहार द्वारा आयोजित आक्रोश मार्च की झलकियां







राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष-48, अंक-04
सितम्बर 2026

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक मण्डल
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05

शैक्षिक परिसरों में लहराया भगवा

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हुए छात्रसंघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी...



संपादकीय	04
ABVP Unscripted: When the Campus Ballot Rewrote the Political Narrative	12
भारतीयता के लिए खतरा हामिद अंसारी की सोच	15
UN overlooks cartographic engineering	18
भारत-अमेरिका संबंधों में रणनीतिक टकराव	20
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 'घोष' स्वर, साधना और संगठन की यात्रा	22
नेपाल में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि पर अभाविप ने व्यक्त की संवेदना	24
अभाविप ने परीक्षा सुधारों को लेकर हाई पावर्ड टास्क फोर्स को भेजे सुझाव	25
महिला शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार की पहल का अभाविप ने किया स्वागत	26
निजी विश्वविद्यालयों की वित्तीय पारदर्शिता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश स्वागतयोग्य : अभाविप	27
शोधार्थियों की लंबित डॉक्टोरल फेलोशिप तत्काल जारी करने की मांग अभाविप ने एनसीईआरटी निदेशक को सौंपा ज्ञापन	28
महिला सुरक्षा को लेकर अभाविप का प्रदर्शन, पुलिस एवं विवि प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग	29
उमर खालिद को 'राष्ट्रवादी' बताकर कांग्रेस ने राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ीः अभाविप	30
शब्द बने स्वर, कविता बनी चेतना-'अक्षरम्' में मुखर हुआ युवा मन	31
छात्र समस्याओं को लेकर अभाविप का हल्लाबोल, कुलपति कार्यालय के घेराव के बाद बनी सहमति	32
आयुष इंटर्नशिप विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में समान वृद्धि की मांग को लेकर अभाविप ने निकाला मार्च	33
छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर अभाविप ने उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन	34
अभाविप ने निकाला प्रतिरोध मार्च, दोषियों पर कार्रवाई की मांग	35
पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं ने लिया सामूहिक संकल्प	36
छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित करे राज्य सरकारः अभाविप	37
हमीरपुर में छात्र गर्जना रैली का आयोजन	38

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

देश भर में छात्र-युवाओं में आक्रोश की एक लहर दिखायी दे रही है। इसके ठोस कारण भी हैं। विद्यार्थियों के ऊपर बढ़ता व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का दबाव, जी-तोड़ मेहनत के बाद प्रश्नपत्रों का लीक हो जाना और उसके चलते परीक्षाएं स्थगित अथवा रद्द होना, साथ ही परीक्षा के रद्द होने के कारण अभिभावकों पर अप्रत्याशित आर्थिक बोझ। इन कारणों से छात्र-युवाओं के मन में क्षोभ इकट्ठा हो रहा था जो जंतर-मंतर पर फूट पड़ा।

स्वाधीनता के बाद से ही देश में खड़े हुए प्रत्येक रचनात्मक छात्र आन्दोलन में अभाविप न केवल भागीदार रही है अपितु अधिकांश में नेतृत्व भी दिया है। यह सर्वमान्य है कि विद्यार्थी युवा होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, अतिशय साहसी होते हैं और हर सही बात के लिए कुछ भी कर गुजरने और सत्य के पक्ष में खड़े होने की कीमत चुकाने को तत्पर होते हैं। अनेक बार ऐसे भी अवसर आते हैं जब छात्रों के इन गुणों का उपयोग नकारात्मक शक्तियां अपने निजी स्वार्थ के लिए करती हैं और छात्र-युवा अंततः अपने को ठगा हुआ अनुभव करते हैं।

कुछ समय पहले किसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश ने गैर जिम्मेदार युवाओं के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए 'कॉकरोच' शब्द का प्रयोग कर दिया। यह पूरी तरह अवांछित था। यह भी निश्चित है कि यह टिप्पणी सभी युवाओं के लिए नहीं थी किन्तु अवसर का लाभ उठाया कुछ राजनैतिक दलों और परदे के पीछे से उन्हें सहयोग कर रहे देशी-विदेशी संस्थानों ने। कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल बना जिसे रातों-रात करोड़ों सब्सक्राइबर भी मिल गए।

स्वाधीनता के बाद से ही देश में खड़े हुए प्रत्येक रचनात्मक छात्र आन्दोलन में अभाविप न केवल भागीदार रही है अपितु अधिकांश में नेतृत्व भी दिया है। यह सर्वमान्य है कि विद्यार्थी युवा होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, अतिशय साहसी होते हैं और हर सही बात के लिए कुछ भी कर गुजरने और सत्य के पक्ष में खड़े होने की कीमत चुकाने को तत्पर होते हैं।

मुद्दा क्योंकि परीक्षा प्रश्नपत्र के लीक होने का था, पीड़ित छात्रों का समर्थन मिला और जंतर-मंतर पर आन्दोलन का मंच सज गया। चूंकि नीट की पुनः परीक्षा की नई तिथि घोषित हो गई थी इसलिए वास्तविक पीड़ित विद्यार्थी पुनः तैयारी में जुट गए और उनकी जगह पर नजर आने लगे लेफ्ट-लिबरल गठजोड़ से जुड़े लोग। शैक्षिक सुधारों की माँग कहीं पीछे छूट गयी और सत्ता विरोध और आजादी के नारे जंतर-मंतर पर गूंजने लगे। उमर खालिद की रिहाई की मांग, अभद्र और अश्लील टिप्पणियों वाले वीडियो वायरल किये जाने लगे और संसद की जगह सड़कों पर फैसले की अराजक घोषणाएं की जाने लगीं।

वास्तविक विद्यार्थी आन्दोलन के बदलते तेवर और बदलते मुद्दों से हतप्रभ रह गए। जिस दिन इन आन्दोलनकारियों ने बिना अनुमति संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया और रोके जाने पर सुरक्षा बलों पर हमला करके 200 से अधिक जवानों और अधिकारियों को घायल कर दिया, उस दिन उनकी आशंका सही साबित हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने इस आन्दोलन से दूरी बना ली। देश भर में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव में अभाविप को विजयी बना कर विद्यार्थियों ने इन आन्दोलनकारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि देश के छात्र-युवा हिंसा और अराजकता का समर्थन नहीं करते। वह अपनी मांगों पर दृढ़ हैं, शैक्षिक जगत की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, पर उपद्रव के बल पर नहीं।

छात्रसंघ चुनावों में परिषद को मिली विजय विद्यार्थियों द्वारा उस पर जताये गए विश्वास का परिचायक है। यह परिषद की आन्दोलन के प्रति रचनात्मक दृष्टि को समर्थन है वहीं यह विश्वास उसे और अधिक जिम्मेदारी से परिसरों में सक्रियता बढ़ाने की प्रेरणा देता है।

असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक पर्व विजयादशमी आभासी जगत में रचे गए मायाजाल को छिन्न-भिन्न कर सत्य की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करेगा। असत्य का तिमिर और कुहासा प्रकाश पर्व दीपावली के आलोक में टिक नही सकेगा, यह विश्वास है।

विविध समाचारों तथा नियमित स्तंभों के साथ यह अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है।

हार्दिक शुभकामना सहित,
आपका
संपादक



इलस्ट्रेशन : एआई

शैक्षिक परिसरों में लहराया भगवा

■ अजीत कुमार सिंह

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हुए छात्रसंघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बार फिर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए जीत का परचम लहराया है। पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मंगलुरु तथा केरल के कोच्चि स्थित त्रिपुनिथुरा के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय समेत उत्तराखंड के अधिकांश महाविद्यालयों तथा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सीनेट एवं छात्रसंघ चुनाव में सभी नौ पदो पर अभाविप को मिली शानदार जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्रशक्ति को झूठे विमर्श और राजनीतिक भ्रम से लंबे समय तक गुमराह नहीं किया जा सकता।

यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जंतर-मंतर के आंदोलनों और छात्रों-युवाओं को लेकर एक विशेष प्रकार का नकारात्मक विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था। छात्रसंघ चुनावों के परिणामों ने इस पूरे विमर्श को करारा जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि देश का विद्यार्थी अपनी समस्याओं, अपने अधिकारों और परिसर के हितों के लिए संघर्ष करने वाले छात्र संगठन के साथ खड़ा है।

देश की राजधानी दिल्ली स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष सहित चार में से तीन प्रमुख पदों पर अभाविप की जीत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की आवाज कौन मजबूती से उठाता है। वहीं पंजाब विश्वविद्यालय में लगातार दूसरी बार अध्यक्ष

पद पर मिली ऐतिहासिक जीत ने अभाविप कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा भर दी है।

उत्तराखंड के अधिकांश महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अभाविप को मिली शानदार जीत छात्रों के विद्यार्थी परिषद पर बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है। प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कालेज सहित विभिन्न परिसरों में मिली जीत ने अभाविप के कार्यों पर मुहर लगा दी है। वहीं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (एमयूएचएस) के छात्रसंघ एवं सीनेट चुनाव में अभाविप ने लगातार तीसरी बार चुनाव में सभी पदो पर जीत का परचम लहराया है।

केरल के कोच्चि स्थित त्रिपुनिथुरा के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अभाविप ने सभी छह पदों पर जीत दर्ज कर एसएफआई के लंबे समय से चले आ रहे कथित वर्चस्व को ध्वस्त कर दिया। वहीं मंगलुरु विश्वविद्यालय के हम्पनकट्टा महाविद्यालय में तमाम राजनीतिक दबाव और कथित सरकारी हथकंडों के बावजूद सभी पदों पर अभाविप की जीत महत्वपूर्ण है।

उत्तराखंड से लेकर केरल और दिल्ली से लेकर पंजाब तक छात्रसंघ चुनावों में अभाविप की लगातार जीत ने तथाकथित 'जेन-जी' के नाम पर छात्रों को लेकर गढ़े जा रहे नकारात्मक विमर्श को करारा तमाचा लगाया है। चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया है कि देश का युवा और विद्यार्थी भ्रम, भय और नकारात्मक राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रहित, छात्रहित और परिसर के मुद्दों पर निर्णायक नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहा है।

डूसू चुनाव में अभाविप की 3-0 से जीत

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने 3-0 से जीत दर्ज करते हुए अध्यक्ष, सचिव और सह-सचिव पद पर विजय हासिल की। अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छावड़ी और सह-सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह निर्वाचित हुए। अभाविप ने इस परिणाम को समरसता, देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम के भाव में विद्यार्थियों के विश्वास की जीत बताया।

अध्यक्ष पद पर अभाविप के यश डबास ने 24,576 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने एनएसयूआई के विजय शंकर मीणा को पछाड़ा, जिन्हें 22,523 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन जीत दर्ज की है। सचिव पद पर अभाविप की रिया छावड़ी



21,650 वोटों के साथ विजयी रहीं, जबकि एनएसयूआई की नम्रता चौधरी को 14,869 वोट मिले। संयुक्त सचिव पद पर अभाविप के लक्ष्य राज सिंह ने 16,615 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। विशेष यादव को 15,778 और एनएसयूआई के गोपाल चौधरी को 15,206 वोट मिले। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए 52 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 18 सितंबर को हुए मतदान में 40.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह पिछले तीन वर्षों में हुआ सर्वाधिक मतदान है। पिछले वर्ष 39.5 प्रतिशत विद्यार्थियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। विभिन्न समय पर कक्षाओं में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की गई।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा और फर्जी माध्यमों से मतदान कराने के प्रयास सामने आए, लेकिन अभाविप कार्यकर्ता संयम के साथ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में डटे रहे। अभाविप में पैनल इंदिरा भवन में बैठकर नहीं बनाए जाते, बल्कि इसकी पूरी सांगठनिक प्रक्रिया निर्धारित है और विद्यार्थियों के मत से लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्याशियों का चयन होता है। संगठनात्मक निर्णय के अनुरूप सभी कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर कार्य किया और डूसू में 3-0 का परिणाम विद्यार्थियों के विश्वास और अभाविप की सांगठनिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे जातिवाद और विभाजन की राजनीति से ऊपर उठकर समरसता के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। भारत का जेन-जी संस्कारवान, राष्ट्रवादी और समरसता में विश्वास रखने वाला जेन-जी है। उन्होंने कहा कि परिणाम ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्यार्थी राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस की राजनीतिक मशीनरी के सहारे छात्र राजनीति में सफलता संभव नहीं है। विद्यार्थियों का विश्वास केवल राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि निरंतर कार्य, विचार और सांगठनिक प्रतिबद्धता से अर्जित किया जाता है और अभाविप को मिला यह जनादेश इसका स्पष्ट प्रमाण है।

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि डूसू चुनाव के परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की राजनीतिक मशीनरी के सहारे छात्र राजनीति में सफलता संभव नहीं है। कांग्रेस की पूरी राजनीतिक मशीनरी, एनएसयूआई, आम आदमी पार्टी और अन्य



यह जीत केवल मेरे पक्ष में दिया गया मत नहीं, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के विश्वास, समरसता और देशभक्ति की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभाजनकारी ताकतों को स्पष्ट संदेश दिया है कि जेन-जी समरसता और राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है। मैं इस विश्वास को जिम्मेदारी में बदलते हुए प्रत्येक विद्यार्थी की आवाज को छात्रसंघ के माध्यम से मजबूती से उठाऊंगा। - यश डबास, नवनिर्वाचित डूसू अध्यक्ष



दिल्ली विश्वविद्यालय का जेन-जी जागरूक है और अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। विद्यार्थियों ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। छात्राओं की सुरक्षा, बेहतर छात्र सुविधाएं, समान अवसर और सकारात्मक अकादमिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना मेरी प्राथमिकता होगी। - रिया छावड़ी, नवनिर्वाचित डूसू सचिव



यह परिणाम अभाविप के प्रति विद्यार्थियों के विश्वास का परिणाम है। संगठन के निर्णय के अनुरूप सभी कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर कार्य किया और विद्यार्थियों ने उस कार्यपद्धति को अपना समर्थन दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस विश्वास को जमीनी कार्य में बदलें और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर उपलब्ध रहें। - लक्ष्यराज सिंह, नवनिर्वाचित डूसू सह-सचिव

संगठनों की सक्रियता के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपना स्पष्ट जनादेश दिया है। छात्र राजनीति में विद्यार्थियों का विश्वास केवल राजनीतिक प्रभाव या संसाधनों के आधार पर नहीं, बल्कि निरंतर कार्य, विचार और विद्यार्थियों के बीच सक्रियता से अर्जित किया जाता है। यह परिणाम उन सभी लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है, जो छात्र राजनीति को बाहरी राजनीतिक प्रभाव के सहारे संचालित करने का प्रयास करते हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय में अभाविप ने लहराया जीत का परचम



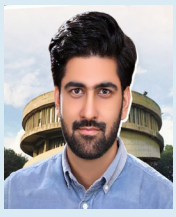
पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (पीयूसीएससी) के चुनाव परिणामों ने पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की छात्र राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के प्रत्याशी अंकित बिधान ने शानदार एवं निर्णायक जीत दर्ज करते हुए लगातार दूसरी बार पंजाब विश्वविद्यालय में अभाविप का परचम लहराया है। अंकित बिधान ने 3,143 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आदिल बराड़ को 506 मतों से पराजित किया।

इस जीत को केवल छात्रसंघ चुनाव का परिणाम नहीं, बल्कि पंजाब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अभाविप के कार्यों, छात्रहित के मुद्दों और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनावों में अभाविप ने लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर नया इतिहास रचा है। पिछले वर्ष अध्यक्ष पद पर गौरववीर सोहेल की जीत के बाद इस वर्ष अंकित बिधान की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में अभाविप की पकड़ मजबूत हुई है।

जीत की घोषणा के बाद अभाविप समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और झंडों के साथ अपना हर्ष व्यक्त किया।

अभाविप ने चुनाव परिणाम को विद्यार्थियों के स्पष्ट जनादेश के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि छात्रों ने चुनाव के दौरान फैलाए गए भ्रम, झूठे प्रचार और नकारात्मक नैरेटिव के बजाय अपने अनुभव और विवेक पर भरोसा किया है। अभाविप के अनुसार, पिछले वर्ष छात्रसंघ अध्यक्ष के रूप में छात्रहित से जुड़े मुद्दों को उठाने, विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने और उनकी आवाज को विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाने का परिणाम इस चुनाव में दिखाई दिया है। अभाविप ने कहा कि अलग-अलग माध्यमों से भय, भ्रम और दुष्प्रचार को राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय की जेन-जी ने इसे स्वीकार नहीं किया।

अभाविप ने कहा कि यह परिणाम उस धारणा का भी उत्तर है कि आज की युवा पीढ़ी राष्ट्रवादी विचारों या अभाविप से स्वाभाविक रूप से दूर है। विद्यार्थियों ने अपने मत के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि जेन-जी को राष्ट्रवाद से नहीं, बल्कि नकारात्मकता से समस्या है।



"यह जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरी जेन-जी की जीत है। पिछले छात्रसंघ द्वारा किए गए कार्यों और विद्यार्थियों के विश्वास के कारण अभाविप को लगातार दूसरी बार यह सफलता मिली है। मैं विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्वच्छ एवं सुरक्षित परिसर सुनिश्चित करने, पारदर्शी प्रशासन और एक बेहतर पंजाब विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हूं।" -अंकित बिधान, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय

मंगलुरु विश्वविद्यालय कॉलेज में सभी छह पदों पर अभाविप की जीत



मंगलुरु विश्वविद्यालय(हम्पनकट्टा) के छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) समर्थित उम्मीदवारों ने सभी छह पदों पर जीत दर्ज की। अभाविप ने इसे छात्रों के बीच संगठन के प्रति बढ़ते विश्वास का प्रमाण बताते हुए कहा कि लगातार मिल रही चुनावी सफलता युवाओं, विशेषकर जेन-जी के बीच संगठन की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है।

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अभाविप कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने परिसर में विजय मार्च निकालकर छात्रों का आभार जताया। विजयी प्रत्याशियों ने कहा कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक हथकंडों और दबावों के बावजूद छात्रों ने अभाविप समर्थित उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम छात्रहित के मुद्दों पर संगठन के वर्षभर सक्रिय रहने और छात्रों के बीच निरंतर काम करने का परिणाम है।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य के महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने का निर्णय लिया था। इसके बाद मंगलुरु विश्वविद्यालय महाविद्यालय, हम्पनकट्टा में हुए छात्रसंघ चुनाव में अभाविप समर्थित उम्मीदवारों ने सभी छह पदों पर जीत दर्ज की।

अभाविप ने छात्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस जीत के साथ छात्रहित के प्रति उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अभाविप छात्रों के विश्वास पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। चुनाव परिणामों ने कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई समेत अन्य छात्र संगठनों को स्पष्ट संदेश दिया है कि छात्र केवल चुनाव के समय सक्रिय रहने वाले संगठनों के बजाय वर्षभर उनके बीच काम करने वाली छात्रशक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं।

केरल में टूटा वामपंथियों का 45 साल पुराना गढ़, अभाविप ने रचा इतिहास

अभाविप ने केरल के त्रिपुनिथुरा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में सभी प्रमुख पदों पर विजय प्राप्त कर वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के लगभग 45 वर्षों पुराने कथित वर्चस्व को समाप्त कर दिया है। यह केवल एक छात्रसंघ चुनाव का परिणाम नहीं है, बल्कि केरल के उस शैक्षिक परिसर में बदलते वातावरण का संकेत है, जहां लंबे समय से वामपंथी छात्र संगठनों का प्रभाव रहा है। चार दशकों से अधिक पुराने एसएफआई के कथित गढ़ को अभाविप ने एक ही चुनाव में ध्वस्त कर दिया। छात्रसंघ चुनाव में अभाविप की स्निग्धा एम. हरि अध्यक्ष चुनी गईं, जबकि आदित्य टी.ए. ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। विग्नेश भट्ट महासचिव चुने गए। इसके अलावा विग्नेश डी. ने पत्रिका संपादक और अंजलि टी. ने कला परिषद सचिव का पद जीता। निवेद्या के.एन. विश्वविद्यालय छात्रसंघ प्रतिनिधि चुनी गईं। शिवानी आर. और अवनी सी.बी. क्रमशः द्वितीय वर्ष स्नातक और द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर प्रतिनिधि चुनी गईं।



अभाविप ने छात्रसंघ के सभी पदों पर विजय प्राप्त कर एसएफआई को पूरी तरह परिसर से बाहर कर दिया। केरल जैसे राज्य में, जहां एसएफआई का छात्र राजनीति में लंबे समय से मजबूत प्रभाव रहा है, वहां इस प्रकार की विजय छात्रों का अभाविप के प्रति विश्वास को दर्शाता है। जानकारी हो कि कोच्चि स्थित त्रिपुनिथुरा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय लंबे समय से एसएफआई के प्रभाव वाले प्रमुख परिसरों में गिना जाता रहा है। वर्षों तक छात्रसंघ की बागडोर वामपंथी छात्र संगठन के हाथों में रही। लेकिन इस बार छात्रों के निर्णय ने महाविद्यालय की छात्र राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया।

अभाविप ने इस विजय को एसएफआई की कथित छात्र विरोधी नीतियों की अस्वीकृति बताया है। अभाविप का कहना है कि एसएफआई के नेतृत्व वाले छात्रसंघों ने संस्कृत भाषा और उससे जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। अभाविप को मिली यह जीत केवल छात्रसंघ के पदों की नहीं है बल्कि महाविद्यालयों में विचार, संस्कृति और छात्र राजनीति की दिशा को लेकर भी है।

उत्तराखंड के छात्रसंघ चुनाव में अभाविप का दबदबा



उत्तराखंड में संपन्न छात्रसंघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने एक बार फिर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रदेश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित डीएवी पीजी महाविद्यालय, देहरादून समेत अनेक महाविद्यालयों एवं शैक्षिक परिसरों में अभाविप प्रत्याशियों ने अध्यक्ष सहित विभिन्न प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की। अभाविप की इस सफलता को कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

अभाविप का कहना है कि छात्र-छात्राओं ने तथाकथित 'झूठ की गूंज' को नकारते हुए ऐसे संगठन पर भरोसा जताया है, जो वर्षभर छात्रहित के मुद्दों को लेकर परिसर में सक्रिय रहता है और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करता है।

राजधानी देहरादून स्थित डीएवी पीजी महाविद्यालय में एक बार फिर अभाविप का परचम लहराया। अध्यक्ष पद पर अभाविप के नवदीप राणा ने एनएसयूआई के सौरभ सेमवाल को 94 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की। चार प्रत्याशियों के बीच हुए मुकाबले में नवदीप राणा की जीत को राजधानी की छात्र राजनीति में अभाविप के प्रभाव के महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। डीएवी पीजी महाविद्यालय में छह पदों के लिए कुल 28 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अध्यक्ष पद पर मिली जीत ने अभाविप के लिए इस प्रतिष्ठित छात्रसंघ में अपनी मजबूत स्थिति को एक बार फिर स्थापित किया है।

देहरादून के एमकेपी पीजी महाविद्यालय में अभाविप ने सभी प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर आयुषी पैन्यूली विजयी रहीं। इसके अलावा उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पदों पर भी अभाविप प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं श्री गुरु राम राय (एसजीआरआर) पीजी महाविद्यालय में भी अभाविप ने छात्रसंघ के सभी प्रमुख पद अपने नाम किए। अध्यक्ष पद पर साहिल पंवार ने 388 मत प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की। महासचिव पद पर रोहित रावत और कोषाध्यक्ष पद पर अर्चना पाल विजयी रहीं। वहीं उपाध्यक्ष, सहसचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पदों पर अभाविप प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। इस प्रकार एसजीआरआर महाविद्यालय का पूरा छात्रसंघ अभाविप के खाते में गया।

मसूरी के एमपीजी महाविद्यालय में भी अभाविप ने अध्यक्ष, महासचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि समेत तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की। प्रदेश के अन्य शैक्षिक परिसरों में भी अभाविप प्रत्याशियों ने प्रभावी

प्रदर्शन किया। हरिद्वार के राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला में अभाविप के सन्नी शर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अमोड़ी राजकीय महाविद्यालय में अभाविप के राम सिंह ने अध्यक्ष पद पर 79 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 116 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 37 मत प्राप्त हुए।

खटीमा के एचएनबी महाविद्यालय में अभाविप के धीरज सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में अभाविप के रोहित कुमल्टा ने एनएसयूआई प्रत्याशी को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की।

कुमाऊं मंडल में अभाविप और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच कई स्थानों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मंडल के 50 महाविद्यालयों में अभाविप ने 16 अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की। देहरादून और गढ़वाल के कई प्रमुख महाविद्यालयों के साथ-साथ कुमाऊं में भी अभाविप ने महत्वपूर्ण सीटों पर सफलता हासिल की।

छात्रहित को प्राथमिकता देने का संकल्प

अभाविप उत्तराखंड के प्रदेश मंत्री यशवंत पंवार ने चुनाव परिणामों को छात्र-छात्राओं के संगठन के प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि छात्रहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। उन्होंने कहा है कि छात्रों ने ऐसे संगठन पर विश्वास जताया है, जो केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे वर्ष परिसर में छात्रों की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर सक्रिय रहता है।

एमयूएचएस छात्रसंघ और सीनेट चुनाव में अभाविप की शानदार जीत

महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (एमयूएचएस) के छात्रसंघ एवं सीनेट चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने सभी नौ पदों पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। अभाविप ने इस विजय का श्रेय विद्यार्थियों के विश्वास, छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाने और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया।

सीनेट के लिए लक्ष्मीकांत होनकलास मोकाशे,आदित्य रामकिसन जयभाय, और शुभंकर नितिन मंगाते निर्वाचित हुए। वहीं छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर रोहित मधुकर माली विजयी रहे। छात्रसंघ के उपाध्यक्ष पद पर यशराज धनंजय काकड़ और मिथिलेश श्रीकृष्ण महोरे, सचिव पद पर ज्ञानेश्वर रावसाहेब आंधले तथा संयुक्त सचिव पद पर केशव शरद पाटील और देवांशी प्रशांत भुराने निर्वाचित हुए।

अभाविप कोंकण प्रांत के प्रदेश मंत्री राहुल राजौरिया ने कहा कि चुनाव परिणाम विद्यार्थियों के अभाविप के कार्यों और विचारों में निरंतर विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न चुनौतियों और संगठन के विरुद्ध बनाए जा रहे कथित विमर्शों के बावजूद विद्यार्थियों ने अभाविप के कार्यों का आकलन कर अपना समर्थन दिया है। सभी नौ पदों पर लगातार तीसरी बार जीत अभाविप कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है, साथ ही यह विद्यार्थियों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ाती है।

अभाविप ने कहा कि चुनाव में विद्यार्थियों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को आगे के कार्यों में प्रतिबिंबित करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि छात्र हितों, शैक्षणिक समस्याओं और उनके अधिकारों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाएंगे। संगठन ने सभी विजयी प्रत्याशियों और चुनाव प्रक्रिया में जुटे कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए महाराष्ट्र के चिकित्सा विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। ■



ABVP Unscripted: When the Campus Ballot Rewrote the Political Narrative

■ **Shravan B. Raj**

There is perhaps no better forum than campus elections to understand the political pulse of India's younger generation. Beyond national campaigns and narratives shaped on social-media platforms, university ballot boxes provide a direct reflection of how students perceive politics, governance and public issues.

It is in this context that the recent electoral victories of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) at the University of Delhi and earlier at Panjab University assume significance beyond the immediate outcomes of campus elections.

These victories came at a time when a strong political narrative was being advanced that India's student community had turned against the ABVP, particularly in the aftermath of the student mobilisation at Jantar Mantar. The subsequent electoral results, however, presented a markedly different picture.

From Punjab to Delhi

The Panjab University student elections were held on August 31, with results announced on September 1. ABVP candidate Ankit Bidhan was elected President, securing 3,149 votes. Adil Brar of the Association of Students for Alternative Politics (ASAP), associated with the Aam Aadmi Party (AAP), received 2,637 votes, while Gurman Singh Sidhu of the Congress-affiliated National Students' Union of India (NSUI) finished third with 2,263 votes.

For the ABVP, the result marked a second consecutive victory at Panjab University.

A similar outcome followed in the Delhi University Students' Union (DUSU) elections, the results of which were announced on September 19. ABVP's Yash Dabas was elected President with 24,576 votes, defeating NSUI's Vijay Shankar Meena, who secured 22,523 votes.

ABVP's Riya Chhabdi was elected Secretary with 21,650 votes, while Lakshya Raj Singh won the Joint Secretary's post with 16,615 votes. The Vice-President's post was won by independent candidate Deepanshu Shokeen, who secured 30,615 votes.

The ABVP therefore secured three of the four central posts at Delhi University. NSUI, which had won one of the four central positions in the previous election, failed to secure any of the central posts this time.

These results warrant a closer examination of the political developments that preceded them.

Jantar Mantar and the CJP

On June 6, 2026, a major student and youth protest was held at Jantar Mantar in New Delhi under the leadership of the Cockroach Janata Party (CJP). The agitation focused on alleged irregularities in the 2026 National Eligibility cum Entrance Test (NEET) and broader concerns surrounding the examination system.

Among the principal demands was the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. The protest was led by CJP founder Abhijit Dipke, while Sonam Wangchuk also joined the agitation through a hunger strike. The protesters also demanded financial assistance for families of students who had died by suicide following the alleged NEET paper leak.

Initially presented primarily as a student-centred agitation, the protest subsequently received support from opposition political parties and leaders, including those associated with the Congress and Left organisations.

By July, the mobilisation had acquired a

more overt political character. The march towards Parliament on July 20 witnessed violence, with reports of individuals described as criminal elements joining the demonstration. On July 23, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Vadra participated in programmes associated with the agitation.

Consequently, an issue that had initially centred on examination-related concerns increasingly became part of a wider political confrontation with the Union government.

When the Generation Spoke Through the Ballot

This sequence of events makes the subsequent campus election results particularly significant.

The Jantar Mantar agitation was initially perceived by many as an expression of genuine student concerns. However, the subsequent participation of Left-wing, Maoist and Congress-aligned student organisations gave the mobilisation a broader political dimension. The argument advanced by these groups was that the agitation represented opposition to the ABVP.

The elections that followed in Delhi and Punjab offered an opportunity to test that political claim through the ballot box.

The ABVP's victories suggest that concerns over examination irregularities and dissatisfaction with aspects of governance can coexist with a strong attachment to national identity, unity and patriotism. Questioning shortcomings within the country's administrative and institutional systems does not necessarily imply rejection of the national framework itself.

This distinction is important. Students can demand accountability, transparency and reform while simultaneously retaining faith in the nation and its democratic institutions.

The electoral results can therefore be read as a rejection of the assumption that every student grievance against the government will automatically translate into electoral support for opposition or Left-wing student organisations.

The Jharkhand Contrast

The contrast becomes more visible when the Jantar Mantar mobilisation is compared with the student agitation in Jharkhand.

Beginning on July 25, students in Jharkhand launched protests over alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations. On August 10, thousands of young people marched peacefully towards the state Assembly in Ranchi. The police attempted to disperse the protesters using tear gas, water cannons and batons.

The agitation was temporarily suspended after the Jharkhand government agreed on August 19 to cancel certain examinations. The protesters also expressed their opposition to the JMM-Congress government through political demonstrations, including the burning of effigies of Chief Minister Hemant Soren and Rahul Gandhi.

Yet many of the political faces and organisations prominently associated with the Jantar Mantar agitation were conspicuously absent from the Jharkhand movement.

This contrast raises an important question: are student issues being supported consistently, or does the level of political mobilisation sometimes depend on which government is being challenged?

The Politics of Double Standards

The differing responses to the two agitations point towards what may be perceived as an inconsistency in the opposition's approach to student issues.

At Jantar Mantar, examination-related grievances were elevated into a major national political campaign against the Union government. In Jharkhand, however, when students raised similar concerns over examination irregularities while the Congress was part of the governing coalition, the issue did not receive a comparable level of national political mobilisation.

The difference does not necessarily invalidate the grievances raised by students in either case. Rather, it raises questions about

the political framing of student movements.

When student protests become platforms for broader political campaigns, students may increasingly begin to examine not only the issue being raised but also the political interests surrounding the mobilisation.

This may help explain why the subsequent campus elections produced results that differed from the narrative that had gained prominence during the Jantar Mantar agitation.

The Left's Electoral Challenge

The DUSU results also highlight the electoral difficulties faced by Left-wing student organisations.

AISA presidential candidate Ananya Rathore secured 5,377 votes, compared with 4,310 votes for NOTA. For the Vice-President's post, AISA-SFI candidate Akshat Shikhar received 2,383 votes, while NOTA secured 4,359 votes.

Similarly, for the Joint Secretary's post, SFI candidate B. Parijath received 5,837 votes, whereas NOTA secured 7,389 votes.

In these contests, NOTA received more votes than the respective candidates supported by Left-wing student organisations. While NOTA cannot be equated directly with support for any particular political organisation, these figures nevertheless demonstrate the difficulty faced by these organisations in converting their political claims into corresponding electoral support.

The results also suggest that students are willing to independently assess competing political narratives rather than automatically aligning themselves with one ideological position.

What the Campus Ballot Says

A reading of campus politics in 2026 therefore points towards a more complex political consciousness among India's younger generation.

Students are willing to question examination systems, demand institutional accountability and protest against administrative failures. At the same time, such concerns do not necessarily translate into rejection of nationalism, patriotism or the broader national framework.

The Jantar Mantar mobilisation, the Jharkhand student agitation and the subsequent ABVP victories in Punjab and Delhi, when viewed together, offer an important lesson: student politics cannot be understood solely through street protests, social-media campaigns or narratives constructed by political organisations.

The ballot box provides another and perhaps more direct, measure of student opinion.

The results also indicate that the younger generation increasingly seeks to evaluate political organisations on the basis of their own experiences and perceptions rather than simply accepting political narratives at face value. Students may support a demand for reform while simultaneously rejecting the political interpretation attached to that demand.

This is the larger significance of the recent campus elections.

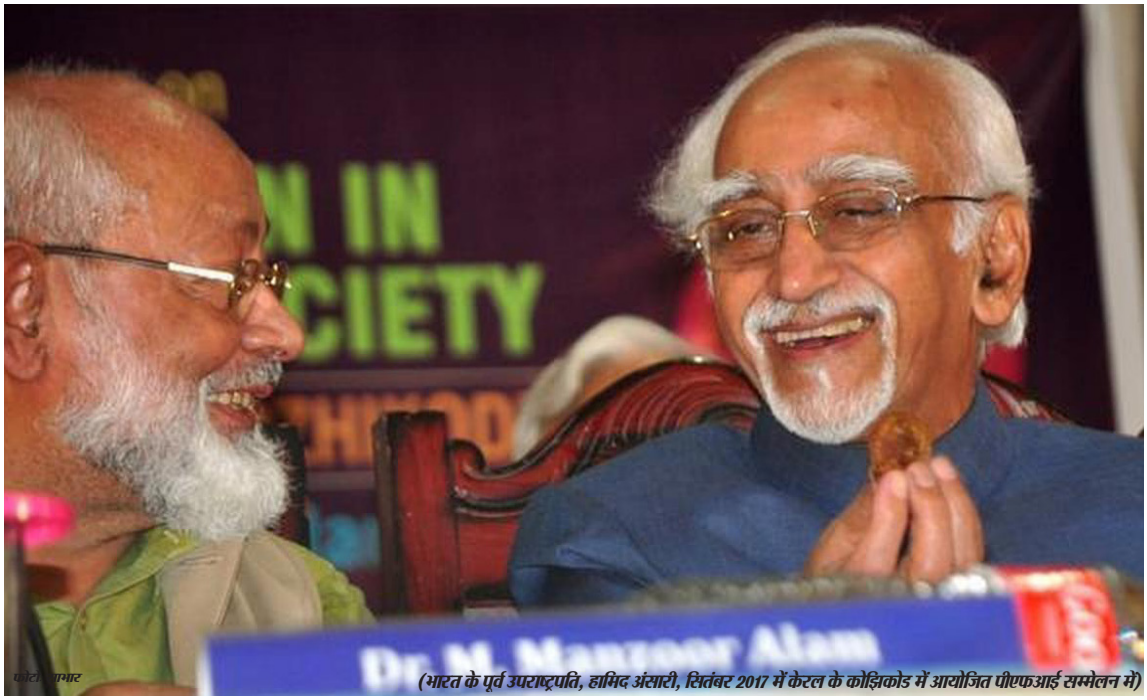
India's students are neither disengaged from questions of governance and accountability nor necessarily willing to be politically mobilised through a single ideological narrative. They are capable of distinguishing between criticism of a government, demand for institutional reform and commitment to the nation.

The campus ballot, therefore, is more than a mechanism for choosing student representatives. It is also a window into how the younger generation is negotiating the relationship between student welfare, political accountability, nationalism and democratic participation.

And in 2026, that ballot has offered a message that political observers would do well to take seriously. ■

(Author is National Secretary of ABVP)

भारतीयता के लिए खतरा हामिद अंसारी की सोच



फोटो : साभार (भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, हामिद अंसारी, सितंबर 2017 में केरल के कोझिकोड में आयोजित पीएफआई सम्मेलन में)

■ विनय कुमार सिंह

उच्च संवैधानिक पदों की गरिमा यह अपेक्षा करती है कि उन पर आसीन व्यक्ति संकीर्णताओं और असामाजिक पूर्वाग्रहों से पूर्णतः मुक्त होकर लोक-कल्याण के प्रति समर्पित रहें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों से देश की जनता और संवैधानिक संस्थाएं अपेक्षा करती हैं कि उनका आचरण निष्पक्ष, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाला तथा संकीर्ण वैचारिक दायरों से परे हो। हालांकि, स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एवं कूटनीतिक इतिहास में कुछ ऐसे दृष्टांत भी सामने आते हैं, जिनकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीय सूचना तंत्र तथा संवैधानिक तटस्थता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की पृष्ठभूमि और उनके कार्यकाल से जुड़े विवाद इसी विमर्श के केंद्र बिंदु रहे हैं।

संवैधानिक मर्यादाओं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के इसी मौलिक प्रश्न की जड़ें हामिद अंसारी के शुरुआती कूटनीतिक करियर के समय से प्रतिबिम्बित होती रही हैं। हामिद अंसारी का सार्वजनिक जीवन भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अधिकारी के रूप में आरंभ हुआ था। वह 1990 के दशक में तेहरान (ईरान) में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत थे। इसी दौर में 'रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' (रॉ) के तेहरान स्थित नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुंचा था। पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी ए. के. सूद तथा वरिष्ठ रक्षा विश्लेषकों द्वारा सार्वजनिक रूप से यह चिंता जताई गई थी कि उस

समय दूतावास के कूटनीतिक प्रबंधन एवं प्राथमिकताओं में हुई गंभीर कमियों के कारण भारतीय सुरक्षा तंत्र के गोपनीय अभियानों तथा एजेंट संदीप कपूर एवं डी. बी. माथुर की पहचान उजागर हुई।

एजेंसी के पूर्व अधिकारियों के बयानों और रिपोर्टों में यह उल्लेख मिलता है कि तेहरान में पदस्थापना के दौरान कुछ ऐसे संवेदनशील मामलों को अनदेखा किया गया, जिससे सीमा पार तथा विदेशी खुफिया नेटवर्क को भारतीय अभियानों की जानकारी मिल सकी। गुप्तचर एजेंसियों के लिए किसी देश में अपने नेटवर्क और अभियानों को स्थापित करने में दशकों की मेहनत लगती है, और ऐसी सूचनाओं का लीक होना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार होता है। कूटनीतिक क्षेत्र में लगी यह आंच केवल विदेश सेवा तक सीमित नहीं रही, इस सच की गूंज को सर्वोच्च सदन में उनके विदाई के समय भी सुना गया।

वर्ष 2017 में जब हामिद अंसारी का उपराष्ट्रपति के रूप में दस वर्षों का कार्यकाल पूर्ण हुआ, तब राज्यसभा में उनके विदाई समारोह के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष वक्तव्य दिया था। प्रधानमंत्री का भाषण कूटनीतिक शब्दावली एवं अर्थपूर्ण व्यंग्य का मिश्रण ही था। प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर कहा था कि अंसारी जी का अधिकांश जीवन कूटनीतिक दायरों, मध्य पूर्व के देशों के वातावरण और विशिष्ट वैचारिक संस्थाओं के बीच बीता है; सार्वजनिक जीवन में रहते हुए सदैव संविधान की मर्यादा एवं दायरे में रहने से एक छटपटाहट भीतर रह गई होगी, किंतु संवैधानिक पद से मुक्त होने के बाद आज से वह संकट नहीं रहेगा। अब आपको अपनी मूलभूत सोच के अनुरूप सोचने एवं कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी।

इस टिप्पणी का निहितार्थ यह था कि जीवन भर एक विशिष्ट राजनीतिक-कूटनीतिक विचारधारा और दायरे में रहने के कारण, उनके निर्णयों और दृष्टिकोण पर वही छाप स्पष्ट नजर आती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद अंसारी की सोच में राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ाव के बजाय एक विशिष्ट वर्गवादी या वैचारिक पूर्वाग्रह की झलक मिलती रही, जिसे संसद में एक प्रकार के शिष्ट व्यंग्य के साथ रेखांकित किया गया था।

संसद की चौखट से बाहर निकलते ही उनका यह वैचारिक पूर्वाग्रह उनकी लिखित कृतियों के माध्यम से और अधिक मुखर होकर देश के सामने आया। उपराष्ट्रपति पद से हटने के तुरंत बाद हामिद अंसारी द्वारा लिखित आत्मकथा 'बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंटः रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ' प्रकाशित हुई। इस पुस्तक और अपने कई साक्षात्कारों में उन्होंने यह दावा प्रस्तुत किया कि भारत में मुस्लिम समुदाय के भीतर असुरक्षा, भय तथा असहजता का भाव उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश में नागरिकता के मूल सिद्धांतों पर प्रश्न चिह्न खड़े हो रहे हैं।

हालांकि, उनके इस दावे की व्यापक आलोचना हुई। आलोचकों और समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया कि जिस देश ने उन्हें लगातार दस वर्षों तक सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर आसीन किया, जिस राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रणाली ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया, उसी देश के सामाजिक वातावरण पर बिना किसी प्रमाणित आंकड़ों के इस तरह के आरोप लगाना अनुचित था। उनकी अपनी पुस्तक में भी इस निष्कर्ष की पुष्टि हेतु कोई ठोस सामाजिक अध्ययन या आधिकारिक डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था। सत्ता में रहते हुए देश का ढांचा सही प्रतीत होना एवं पद से हटते ही सामाजिक दरार का राग अलापना, उनके दृष्टिकोण की प्रामाणिकता पर प्रश्न खड़े करता है।

सिर्फ वैचारिक स्तर पर सामाजिक वैमनस्य का वातावरण बनाना ही नहीं, बल्कि संदिग्ध एवं आपराधिक तत्वों के प्रति उनका ढुलमुल रवैया भी अत्यंत चिंताजनक रहा है। हामिद अंसारी के सार्वजनिक जीवन का एक और विवादित पहलू दुर्दांत गैंगस्टर और माफिया नेता मुख्तार अंसारी के प्रति उनका दृष्टिकोण और पारिवारिक संबंध रहा है। पूर्वांचल में आतंक, हत्या और अवैध वसूली का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी के आपराधिक साम्राज्य को लेकर पूरा देश अवगत रहा है। बिहार पुलिस के पूर्व महानिदेशक (डीजीपी) डी.पी. ओझा की आधिकारिक रिपोर्टों और जांच निष्कर्षों में यह बात खुलकर सामने आई थी कि मुख्तार अंसारी का नेटवर्क न केवल क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय था, बल्कि उसने मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे खतरनाक अपराधियों की तर्ज पर समानांतर अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया था।

डी.पी. ओझा की रिपोर्टों में मुख्तार अंसारी नेटवर्क के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (आईएसआई) एवं दाऊद इब्राहिम गैंग के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नेटवर्क, जैसे अता-उर-रहमान उर्फ सिकंदर उर्फ बाबू से जुड़े होने के गंभीर तथ्य सामने आए थे। इसके बावजूद, सार्वजनिक तथा कूटनीतिक जीवन में रहते हुए हामिद अंसारी ने मुख्तार अंसारी के इस संगठित अपराध चक्र और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर कभी कोई कठोर रुख नहीं अपनाया, बल्कि उन पर अपने प्रभाव का उपयोग करके इस आपराधिक कुनबे को अप्रत्यक्ष रूप से बचाने और संरक्षण देने के आरोप लगते रहे।

हामिद अंसारी ने कूटनीतिक शिथिलताओं, माफिया गिरोहों के प्रति उदारता, कट्टरपंथी संगठनों के मंचों की शोभा बढ़ाने और निराधार आरोपों के माध्यम से स्वयं यह निश्चित किया है कि भारतीय इतिहास और जनमानस उन्हें किस रूप में याद रखेगा। इतिहास का न्याय निर्मम होता है और वह पदों के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में किए गए कार्यों और निष्ठा के आधार पर व्यक्तियों का अंतिम मूल्यांकन करता है।

अपराधिक सिंडिकेट्स के प्रति इस मौन स्वीकृति का अगला चरण देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले कट्टरपंथी संगठनों के साथ सार्वजनिक मंच साझा करने के रूप में दिखा। पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), जिसे भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और देश की अखंडता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के कारण प्रतिबंधित किया है। इस संस्था के कार्यक्रमों में पूर्व उपराष्ट्रपति की उपस्थिति ने भी राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा किया था।

उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों और प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017 में कोझिकोड (केरल) में आयोजित पीएफआई से जुड़े मंचों पर हामिद अंसारी की उपस्थिति दर्ज की गई थी। केरल पुलिस की आंतरिक सुरक्षा जांच टीम (आईएसआईटी) तथा महाराष्ट्र एटीएस की रिपोर्टों के अनुसार, पीएफआई के तार अल-कायदा, लश्कर-ए-तय्यबा (LeT) और अन्य प्रतिबंधित जिहादी संगठनों से जुड़े हुए पाए गए थे। एक पूर्व उपराष्ट्रपति का ऐसे संगठनों के सार्वजनिक सम्मेलनों में मुख्य अतिथि या प्रतिभागी के रूप में शामिल होना, देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति एक अत्यंत चिंताजनक रवैये को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, ज़िया-उल-हक के दौर के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों एवं वैश्विक मंचों पर उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने भी भारत विरोधी ताकतों को अनजाने में बल प्रदान किया।

इतिहास के इन विवादित पन्नों के आलोक में जब हम राष्ट्र के वास्तविक नायकों को देखते हैं, तो आदर्श और निष्ठा का अंतर सर्वथा स्पष्ट हो जाता है। भारतवर्ष की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना ने सदैव उन विभूतियों को अपना सच्चा नायक और आदर्श माना है, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की रक्षा और सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत की धरती पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जैसे वीर हुए, जिन्होंने 1948 में नौशेरा की जंग में भारत की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस देश ने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई में राष्ट्रीय एकता का संगीत सुना है और मिसाइल मैन डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के रूप में एक ऐसे राष्ट्रपति को देखा है, जिन्होंने अपनी हर सांस राष्ट्र की वैज्ञानिक और नैतिक प्रगति को समर्पित कर दी।

विदेशी ताकतों की भाषा बोलना, भारत की धरती पर रहकर, भारत के संवैधानिक संसाधनों और सम्मान को प्राप्त करके भी भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव पर चोट पहुंचाना कभी भी इस देश का आदर्श नहीं हो सकता। हामिद अंसारी ने कूटनीतिक शिथिलताओं, माफिया गिरोहों के प्रति उदारता, कट्टरपंथी संगठनों के मंचों की शोभा बढ़ाने और निराधार आरोपों के माध्यम से स्वयं यह निश्चित किया है कि भारतीय इतिहास और जनमानस उन्हें किस रूप में याद रखेगा। इतिहास का न्याय निर्मम होता है और वह पदों के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में किए गए कार्यों और निष्ठा के आधार पर व्यक्तियों का अंतिम मूल्यांकन करता है। ■

UN overlooks cartographic engineering

■ K N Pandita

For over 450 years, the standard world map used in classrooms, atlases, and digital platforms has been based on the Mercator projection, created by Flemish cartographer Gerardus Mercator in 1569. While the Mercator map was an incredible tool for 16th-century nautical navigation because it preserved straight compass bearings, it mathematically creates massive distortions near the poles. As a result, landmasses in the Global North appear disproportionately massive, while equatorial regions are visually shrunk. For example: on a Mercator map, Greenland looks roughly the same size as the continent of Africa. In reality, Africa is larger 14 times than Greece. In reality, Greenland covers 2.16 million sq km. Africa covers 30.3 million, nearly 14 times as much. Even India, at 3.29 million sq km, is bigger than Greenland, but the maps as of now suggest otherwise.

Designed primarily for maritime navigation, the Mercator map preserves angles and direction but severely distorts the relative size of landmasses as they approach the poles. While it was functional for European sailors charting trade routes during the Age of Discovery, its prolonged dominance as an educational tool has institutionalized a warped worldview.

The most egregious consequence of this projection is the dramatic underrepresentation of the Global South, particularly Africa. On a standard Mercator map, Africa appears roughly equivalent in size to Greenland. In geographic reality, Africa is 15 times larger than Greenland.

Cartographic distortion fosters an insidious psychological bias. When generations of schoolchildren grow up viewing a world where Europe and North America dwarf the rest of the globe, it subtly conditions a perception of inherent cultural, economic, and geopolitical superiority.

Resolution

On September 4, the United Nations General Assembly (UNGA) passed a historic, non-binding resolution titled 'Correct the Map: Rebalancing Global Cartographic Representation and Promoting Equitable Representation of the World's Regions, Particularly Africa'. Sponsored by Togo, spearheaded by the African Union, and passed with an overwhelming 164-to-1 vote, this landmark decision formally encourages the global community to move away from the centuries-old Mercator projection towards the 2018 Equal Earth map projection. The United States cast the sole dissenting vote, and there were six abstentions: Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova, Serbia, and Ukraine.

While legally non-binding, the resolution represents a profound shift in international relations, signalling a collective commitment to undoing the psychological and structural remnants of Eurocentric cartography. By challenging how the world visually conceptualises power and geography, the UN has initiated a long-overdue decolonisation of the global mind.

Rabah Arezki, a former World Bank economist, writing in Le Monde, argued that the Mercator projection historically served as a political tool. 'The standard projection was a political tool that contributed to the scramble for Africa, also known as the partition of Africa when Western European powers colonized the continent,' he wrote. 'Just as making Africa look small and conquerable then, the Mercator projection makes the continent look small and irrelevant now.'

The entire continent of Africa covers approximately 30.3 million square kilometres-a vast expanse capable of comfortably containing the contiguous United States, China, India, Japan, and most of Europe combined. By shrinking the African continent and expanding northern territories, the Mercator projection has implicitly reinforced colonial-era hierarchies, visually diminishing the physical prominence and geopolitical weight of developing nations.

This framing resonates with leaders outside Africa as well. Dorbrene O'Marde, Vice Chair of the Caribbean Community (CARICOM) Reparations Commission, described support for the Equal Earth projection as a

rejection of the Mercator map's 'ideology of power and dominance.'

India voted in favour

India welcomed the Correct the Map Resolution passed by the UN General Assembly on September 4, 2026, noting that traditional maps diminish the perceived sizes of Africa, Latin America, and South Asia. The move aligns with backing developing regions and the African Union's push for accurate geographical scaling instead of 16th century navigational distortions. India clarified that its vote endorsed the general use of equal-area map projections rather than binding the country to any specific projection style like Equal Earth. In a press release, the External Affairs Ministry spokesman, Randhir Jaiswal said, 'the UN General Assembly adopted a resolution titled 'Correct the Map Rebalancing Global Cartographic Representation and Promoting Equitable Representation of the World's Regions, Particularly Africa' on 4th of this month. He said the purpose of this is to encourage the use of equal-area map projections that preserve the relative sizes of continental land mass. The Spokesperson said, India voted in favour of the resolution and also made an explanation of vote stressing on the underlying principle of promoting equal-area cartographic representation. He highlighted that the resolution does not constitute endorsement of any specific map, projection, or depiction of national boundaries. India clarified that its vote endorsed the general use of equal area map projections rather than binding the country to any specific projection style like equal earth.

The controversy

Following the release of maps by UN Geospatial, objection arose in India because regions like Arunachal Pradesh and Aksai Chin were not shown in accordance with official Indian maps. Instead, they were marked using separate 'Indian line' and 'Chinese line' claim designations, creating ambiguity over sovereign borders. Additionally, while the map provided an explanatory dotted note for the Line of Control (LoC) with Pakistan, it lacked similar clarifying caveats for the India-China claim lines

India's stand justified

India rejected the by map issued UN Geospatial on a number of counts. First, the terms of reference were that the UN Geospatial will draw a map which exactly shows the land mass of a country exactly what its size is neither less nor more. It had no business to demarcate the land by drawing red lines and then adding note separately about the ownership as has been done in the case of Arunachal Pradesh and Aksai Chin. Secondly, the map of UN Geospatial is non-binding and India rejected it. The recommendation of the UN GA that the UN Geospatial map should be adopted by the libraries, universities, schools and educational institutions is null and void because it is non-binding. Thirdly, while voting in favour of the resolution on Sept 4, India clarified two essential points. One, Sovereignty was Non-Negotiable. The Ministry of External Affairs emphasized that the non-binding resolution does not authenticate any specific map or address political boundaries. Second, India firmly stated that its sovereign territory --- including the Union Territories of Jammu and Kashmir, and Ladakh- must strictly follow India's official map, calling any misleading depictions unacceptable.

India's stand was vindicated by Ireland whose representative made almost an identical statement. Speaking on behalf of the bloc, Ireland stressed that the measure applied only to the relative size of landmasses and had no bearing on sovereignty, territorial status or internationally recognized borders.

Tailpiece

The cartographic engineer done in the case of Arunachal Pradesh and Aksai Chin regions is blatant violation of the terms of reference. It could be done only on prompting by interested source. It is sad that demands by a majority of members to bring about drastic reforms in the UN. It is dominated by certain vested interests and directed by money power. China invaded Arunachal in 1962 and a year later, it clandestinely obtained Aksai Chin from Pakistan which had been illegally occupying a part of the territory of the State of Jammu and Kashmir that had legally acceded to the Indian Union. China and Pakistan in combination have been conspiring disintegration of the State of Jammu and Kashmir.

Failing to annex Arunachal by force of arms, Beijing is now using other underhand methods to strengthen its illegal claims. It is sad that an organization that was supposed to maintain the high levels of impartiality has lost its reputation and is looked at with a big question mark by most of its member states. ■



इलस्ट्रेशन : एआई

भारत-अमेरिका संबंधों में रणनीतिक टकराव

■ डा. अभिषेक श्रीवास्तव

भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं। औद्योगिक विकास, परिवहन, विनिर्माण और नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध और किफायती आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूस से तेल खरीदना भारत की इसी व्यापक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा रही है।

रूसी तेल के आयात को लेकर अमेरिकी दबाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। रूस- यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका द्वारा रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर कठोर टैरिफ लगाने की पहल ने भारत के सामने एक जटिल परिस्थिति उत्पन्न की है, हालांकि भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय आवश्यकताओं, आर्थिक हितों और आपूर्ति की विश्वसनीयता के आधार पर लिए जाएंगे। किसी भी संप्रभु देश की तरह भारत को भी अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था के हितों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों का चयन करने का पूरा अधिकार है। यदि भारत को अपेक्षाकृत किफायती आपूर्ति के विकल्पों से दूर जाने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इसका प्रभाव घरेलू उत्पादन लागत, महंगाई और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए ऊर्जा विविधीकरण और विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना रणनीतिक आवश्यकता है।

भारत की ऊर्जा नीति किसी एक देश के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिरता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संचालित होती है। भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध दोनों देशों की समृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी बाजार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, वस्त्र,

इंजीनियरिंग उत्पादों और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

दूसरी ओर, भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए एक विशाल उपभोक्ता बाजार, निवेश केंद्र और विनिर्माण साझेदार के रूप में उभर रहा है, ऐसी परिस्थिति में यदि अमेरिका अत्यधिक टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंधों का सहारा लेता है, तो उसका प्रभाव केवल भारतीय निर्यातकों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अमेरिकी आयातकों को भी महंगे उत्पादों, वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों और बढ़ती कारोबारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक संबंधों में अस्थिरता से अमेरिकी कंपनियों की भारतीय बाजार में दीर्घकालिक निवेश योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

भारत के लिए यह परिस्थिति अपने आर्थिक संबंधों को व्यापक बनाने का भी अवसर प्रस्तुत करती है। हालिया मुक्त व्यापार समझौते ने भारतीय कारोबारियों को यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य उभरते बाजारों के साथ व्यापारिक सहयोग बढाने का विकल्प भी दिया है। भारत निर्यात के नए रास्ते विकसित कर सकता है, घरेलू विनिर्माण, उत्पादन क्षमता और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन देकर भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी दबावों का सामना करने में अधिक सक्षम हो सकती है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह व्यापारिक वार्ताओं में अपने हितों की रक्षा करे और आर्थिक विविधीकरण को दीर्घकालिक प्राथमिकता बनाए क्योंकि इस प्रकार की अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों का प्रभाव न सिर्फ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर पड़ेगा बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र वर्तमान वैश्विक भू-राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति में भारत का सहयोग महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति, सामरिक संपर्क और क्षेत्रीय सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। हिंद महासागर में भारत की भौगोलिक स्थिति और नौसैनिक क्षमताएं उसे क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण भागीदार बनाती हैं। समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा, समुद्री डकैती का मुकाबला, मानवीय सहायता, आपदा राहत और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर दोनों देशों के हित जुड़े हुए हैं। भारत की सक्रिय भागीदारी से क्षेत्रीय सहयोग के अनेक अवसर विकसित होते हैं।

चीन के साथ अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत की क्षेत्रीय उपस्थिति, आर्थिक क्षमता और रणनीतिक साझेदारियां हिंद-प्रशांत में शक्ति संतुलन से संबंधित व्यापक विमर्श का हिस्सा हैं। ऐसे में भारत के साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाए रखना अमेरिका के अपने दीर्घकालिक हितों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका व्यापारिक विवादों और आर्थिक प्रतिबंधों को रणनीतिक संबंधों पर प्राथमिकता देता है, तो इससे द्विपक्षीय समन्वय प्रभावित हो सकता है।

आगे की रणनीति में ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, घरेलू रक्षा उत्पादन, महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता, निर्यात बाजारों का विस्तार और बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी शामिल होनी चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका के साथ व्यापारिक मतभेदों को बातचीत और पारस्परिक समझ के माध्यम से सुलझाने के प्रयास जारी रहने चाहिए। भारत की विदेश नीति का मूल आधार राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र निर्णय लेना है और रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ किसी एक शक्ति से दूरी बनाना या किसी दूसरे गुट के साथ पूर्ण रूप से जुड़ना नहीं है। इसका वास्तविक आशय विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ सहयोग करते हुए अपनी निर्णय क्षमता और नीतिगत स्वतंत्रता बनाए रखना है। भारत के लिए रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध, अमेरिका के साथ तकनीकी तथा सामरिक सहयोग और यूरोप सहित अन्य क्षेत्रों के साथ आर्थिक साझेदारियां एक व्यापक विदेश नीति के विभिन्न आयाम हैं। इन संबंधों में संतुलन बनाए रखना भारत की बदलती वैश्विक भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्षतः यह देखें तो ट्रंप की दबाव आधारित नीतियां भारत के आर्थिक हितों, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के सामने चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। लेकिन भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता, व्यापक वैश्विक साझेदारियां और स्वतंत्र विदेश नीति उसे अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती हैं। अमेरिका के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि वह भारत को केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या प्रतिबंधों के दृष्टिकोण से न देखे। हिंद-प्रशांत की स्थिरता, तकनीकी सहयोग, आर्थिक विकास और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे विषयों पर भारत की भूमिका दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। ■

(लेखक, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली में सहायक अध्यापक है)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 'घोष' स्वर, साधना और संगठन की यात्रा



■ डा. मूलचन्द्र सिंह

जब अनेक वाद्य एक लय में बजते हैं, अनेक कदम एक गति से बढ़ते हैं और व्यक्तिगत कौशल सामूहिक अनुशासन में रूपांतरित हो जाता है, तब **'घोष'** केवल संगीत नहीं रहता-वह संगठन की सामूहिक अभिव्यक्ति बन जाता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति में शाखा, गणवेश, व्यायाम, खेल, प्रार्थना और पथ संचलन की तरह 'घोष' ने भी समय के साथ एक विशिष्ट स्थान बनाया है। सामान्य अर्थ में इसे बैंड या वाद्य-वृंद कहा जा सकता है, किंतु संघ की परंपरा में घोष का आशय केवल वाद्य बजाने से नहीं है, बल्कि इसमें संगीत के साथ अनुशासन, अभ्यास, एकाग्रता, समन्वय और सामूहिकता जुड़ी हुई है।

संघ के लगभग एक शताब्दी के इतिहास को देखें तो घोष की यात्रा भी उसके संगठनात्मक विस्तार के साथ विकसित होती दिखाई देती है। प्रारंभिक बिगुल और पथ संचलन से शुरू हुई यह परंपरा आगे चलकर विविध वाद्यों, रचनाओं और बड़े सामूहिक प्रदर्शनों तक पहुंची।

23 अक्टूबर 1928 को विजयादशमी के अवसर पर हुए पथ संचलन में 600 से अधिक गणवेशधारी स्वयंसेवकों के संचलन और **मार्तंडराव जोग** द्वारा बिगुल बजाए जाने का उल्लेख मिलता है। यह छोटा-सा आरंभ आगे चलकर एक विस्तृत परंपरा का आधार बना। संचलन में घोष जुड़ने से कदमों की गति को लय मिली और सार्वजनिक कार्यक्रम में दृश्य अनुशासन के साथ श्रव्य अनुशासन भी दिखाई देने लगा।

गांधीजी की नागपुर सभा और स्वयंसेवकों की उपस्थिति

प्राप्त स्रोतों के अनुसार **5 नवंबर 1933** को नागपुर में महात्मा गांधी की सभा की व्यवस्था में संघ से जुड़े

स्वयंसेवक उपस्थित थे और मार्तंडराव जोग घोष के साथ वहां पहुंचे थे।

1937 : विजयादशमी उत्सव

संघ की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के इतिहास में **1937 के विजयादशमी उत्सव** के विशाल संचलन में घोष के प्रदर्शन का भी उल्लेख मिलता है।

26 जनवरी 1963 : भारत-चीन युद्ध के बाद आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में लगभग **3,000 स्वयंसेवकों ने गणवेश और घोष (बैंड) के साथ भाग लिया।**

30 नवंबर 1986 को दिल्ली में आयोजित एक बड़े पथ संचलन में हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया तथा घोष दल भी संचलन का हिस्सा था। ऐसे बड़े संचलनों में घोष की भूमिका केवल संगीत प्रस्तुत करने की नहीं होती। वह पूरे संचलन की गति और वातावरण को लय प्रदान करता है।

श्री गुरुजी जन्मशताब्दी और घोष

2006-07 में माधव सदाशिव गोलवलकर 'श्री गुरुजी' की जन्मशताब्दी के अवसर के निमित्त दिल्ली के जापानी पार्क में हुए समापन कार्यक्रम से पहले एक विशाल घोष वर्ग और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी आयोजित हुआ।

यह उस लंबी यात्रा का उदाहरण है जिसमें कभी सीमित संख्या में वादकों से शुरू हुई घोष परंपरा आगे बड़े प्रशिक्षण वर्गों और सार्वजनिक प्रस्तुतियों तक पहुंची।

26 फरवरी 2025 : भुवनेश्वर में अखिल भारतीय घोष दिवस

2025 की महाशिवरात्रि के अवसर पर एक हजार से अधिक स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में भाग लिया। घोष वादकों ने विभिन्न वाद्यों के साथ संगीत प्रस्तुत किया और संचलन ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर की परिक्रमा से भी जुड़ा।

इस आयोजन का महत्व केवल उसकी संख्या में नहीं था। यह इस बात का उदाहरण था कि लगभग एक शताब्दी पुरानी घोष परंपरा आज भी प्रशिक्षण, सार्वजनिक संचलन और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से जारी है।

घोष की विशेषताएं एवं महत्व :

1. संगीत से अधिक समन्वय

किसी वाद्य को अकेले बजाना एक प्रकार का कौशल है, लेकिन दर्जनों या सैकड़ों वादकों के साथ निश्चित ताल और गति में बजाना दूसरी प्रकार की साधना है। एक वादक की छोटी-सी असावधानी भी पूरे समूह की लय को प्रभावित कर सकती है। इसलिए घोष अभ्यास में स्वाभाविक रूप से **एकाग्रता, समयबद्धता, धैर्य, निरंतर अभ्यास और परस्पर समन्वय** की आवश्यकता पड़ती है।

यही कारण है कि संघ में घोष को केवल मनोरंजन की गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाता। संगठन की अपनी व्याख्या में इसे व्यक्तित्व और सामूहिक अनुशासन के प्रशिक्षण से जोड़ा जाता है।

2.संगठनात्मक व्यवहार

किसी घोष दल में अनेक वादक होते हैं। प्रत्येक के हाथ में अलग वाद्य हो सकता है, उसकी ध्वनि अलग हो सकती है और उसकी भूमिका भी अलग हो सकती है। फिर भी कोई वादक अपनी इच्छा से गति नहीं बदल सकता। उसे दूसरों को सुनना पड़ता है, संकेत को समझना पड़ता है और अपनी भूमिका को पूरे समूह के अनुरूप रखना पड़ता है। इस अर्थ में घोष '**व्यक्ति और समूह' के संबंध का व्यावहारिक प्रशिक्षण** भी बन जाता है।

3.स्वर से संस्कार

1928 के नागपुर के प्रारंभिक संचलन से लेकर 2025 के भुवनेश्वर घोष दिवस तक देखें तो घोष ने लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में वाद्य बदले, रचनाएं विकसित हुईं, प्रशिक्षण का विस्तार हुआ और प्रस्तुतियों का आकार भी बढ़ा; किंतु इसका केंद्रीय तत्व बना रहा- **सामूहिक लय और अनुशासन।** यही 'घोष' की विशेषता है-**स्वर अनेक, लय एक।**

इसीलिए संघ के संदर्भ में घोष को केवल 'बैंड' कहना उसके पूरे स्वरूप को व्यक्त नहीं करता। यह संगीत है, लेकिन संगीत के साथ प्रशिक्षण भी है; यह सार्वजनिक प्रस्तुति है, लेकिन उसके पीछे लंबे अभ्यास की प्रक्रिया भी है।

अतः संघ का घोष **स्वर और ताल के माध्यम से सामूहिक अनुशासन की अभिव्यक्ति** है-जहां प्रत्येक वादक की भूमिका महत्वपूर्ण होते हुए भी अंतिम प्रभाव पूरे समूह की एकता और समन्वय से उत्पन्न होता है। यही विशेषता इसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। ■

(लेखक, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली में सहायक प्राध्यापक हैं।)

नेपाल में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि पर अभाविप ने व्यक्त की संवेदना

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धादिङ जिलों में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्राकृतिक आपदा के कारण बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने तथा अनेक परिवारों के सामने उत्पन्न कठिन परिस्थितियों पर अभाविप ने चिंता व्यक्त की है। बाढ़ के कारण तीर्थयात्रियों सहित कई लोगों के लापता होने तथा अस्पतालों, विद्यालयों, पुलिस चौकियों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर भी अत्यंत चिंताजनक है।



अभाविप ने कहा कि संकट की इस घड़ी में वह नेपाल के अपने बंधु-भगिनियों के साथ खड़ी है। अभाविप ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सभी लापता लोगों की शीघ्र तलाश और सुरक्षित वापसी की कामना की। साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करते हुए पीड़ितों तक आवश्यक सहायता शीघ्र पहुंचाने की अपील की।

अभाविप ने भारत सरकार द्वारा नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 10 टन राहत सामग्री विमान के माध्यम से तत्काल भेजे जाने के निर्णय का स्वागत किया। अभाविप ने कहा कि भारत सरकार की यह त्वरित सहायता संकट की घड़ी में प्रभावित लोगों तक आवश्यक राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा भारत-नेपाल के आत्मीय संबंधों को और मजबूत करेगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि नेपाल में आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है। संकट की इस घड़ी में अभाविप नेपाल के प्रभावित बंधु-भगिनियों के साथ पूरी संवेदना और एकजुटता के साथ खड़ी है। भारत सरकार द्वारा 10 टन राहत सामग्री तत्काल नेपाल भेजने का निर्णय सराहनीय है। इस त्वरित सहायता से प्रभावित लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने और राहत कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। हमारी प्रार्थना है कि सभी लापता लोगों का शीघ्र पता चले तथा राहत एवं बचाव कार्यों के माध्यम से प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता जल्द से जल्द प्राप्त हो। भारत और नेपाल के बीच के आत्मीय संबंधों की भावना के अनुरूप हम इस कठिन समय में नेपाल के लोगों के साथ हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

अभाविप ने परीक्षा सुधारों को लेकर हाई पावर्ड टास्क फोर्स को भेजे सुझाव

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय एवं विद्यार्थी हितैषी बनाने की दिशा में पहल करते हुए हाई पावर्ड टास्क फोर्स के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि को सुझाव भेजा है। अभाविप ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) सहित महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक सुधारों के साथ-साथ दीर्घकालिक स्तर पर परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है। परीक्षा सुधारों को लेकर अभाविप ने पुणे, नागपुर, भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़ और दक्षिण बिहार में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विद्यार्थियों एवं विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। इन चर्चाओं से प्राप्त सुझावों एवं अनुभवों के आधार पर अभाविप ने परीक्षा व्यवस्था में तत्काल, मध्यम अवधि तथा दीर्घकालिक सुधारों को लेकर एक व्यापक सुझाव-पत्र तैयार किया है।

अभाविप ने महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को दो चरणों में आयोजित करने का सुझाव दिया है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में अभ्यर्थियों की प्रारंभिक छंटनी तथा द्वितीय चरण में अंतिम चयन के लिए परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। अभाविप ने एक ही परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता कम करने तथा चयन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने पर भी बल दिया है। इसके साथ ही नीट को वर्ष में दो बार आयोजित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर बेहतर स्कोर को मान्यता देने, परीक्षाओं को कम्प्यूटर आधारित बनाने, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा परीक्षा केंद्रों के लिए समान राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।

सुझाव-पत्र में अभ्यर्थियों की पहचान एवं सत्यापन, आंकड़ों की सुरक्षा, उत्तर कुंजी, अंकों के सामान्यीकरण, समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वरीयता-निर्धारण व्यवस्था तथा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। तकनीकी अथवा प्रशासनिक गड़बड़ी की स्थिति में स्पष्ट कार्यविधि निर्धारित करने, स्वतंत्र सुरक्षा एवं प्रक्रिया ऑडिट, राष्ट्रीय प्रश्न बैंक, डिजिटल मूल्यांकन, एकीकृत परीक्षा प्रबंधन प्रणाली और केंद्रीय परीक्षा डैशबोर्ड की व्यवस्था तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्परीक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया गया है।

दीर्घकालिक सुधारों के तहत पाठ्यक्रम, शिक्षण, मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए संस्थागत शिक्षण को मजबूत करने, करियर काउंसलिंग एवं योग्यता-आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देने तथा बड़े सुधारों को पायलट, परीक्षण, समीक्षा और स्वतंत्र ऑडिट के बाद चरणबद्ध रूप से लागू करने का सुझाव दिया गया है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें विद्यार्थी की मेहनत और क्षमता का सही मूल्यांकन हो तथा उसे परीक्षा से लेकर चयन तक अनावश्यक दबाव और अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। उनका सुझाव है कि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को दो चरणों में किया जाए। पहले चरण में प्रारंभिक छंटनी हो और दूसरे चरण में अंतिम चयन के लिए परीक्षा हो। इससे चयन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और विद्यार्थियों को अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा।

अभाविप ने अपने सुझाव केवल तत्काल सुधारों तक सीमित नहीं रखे हैं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक बदलाव के लिए भी एक व्यापक

रूपरेखा सामने रखी है। उन्होंने अपने सुझाव उच्चस्तरीय कार्यबल को भेजे हैं। यदि समिति उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित करती है, तो वे इन सुझावों के आधार पर विस्तृत योजना और व्यावहारिक प्रारूप के साथ अपनी बात रखेंगे। उनका उद्देश्य ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाना है, जिसमें हर विद्यार्थी को समान अवसर मिले, किसी तकनीकी या प्रशासनिक कमी के कारण उसे परेशान न होना पड़े और परीक्षा प्रणाली के प्रति विद्यार्थियों एवं समाज का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। परीक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें विद्यार्थी की मेहनत और क्षमता का सही मूल्यांकन हो तथा उसे परीक्षा से लेकर चयन तक अनावश्यक दबाव और अनिश्चितता का सामना न करना पड़े तथा परीक्षा प्रणाली पर विद्यार्थियों एवं समाज का भरोसा मजबूत हो। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। बिहार ।

महिला शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार की पहल का अभाविप ने किया स्वागत

बिहार सरकार द्वारा शोध छात्राओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये फेलोशिप देने, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'अभया ब्रिगेड' (पुलिस दीदी) की शुरुआत किए जाने के निर्णय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दक्षिण बिहार प्रांत ने स्वागत किया है। अभाविप ने कहा कि महिला शिक्षा, शोध और सुरक्षा से जुड़े इन विषयों को लेकर अभाविप पूर्व में ही अपने प्रस्तावों के माध्यम से आवाज उठाता रहा है।

शोध छात्राओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये की फेलोशिप प्रदान करने के निर्णय को अभाविप ने उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। आर्थिक सहयोग मिलने से शोधरत छात्राओं को अपने अध्ययन एवं शोध कार्य को अधिक सुचारु ढंग से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी तथा वे शोध के क्षेत्र में बेहतर अवसरों का लाभ उठा सकेंगी।

वहीं महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय का स्वागत करते हुए अभाविप ने कहा कि इससे बिहार की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के नए अवसर सृजित होंगे। सुरक्षित और सहज शैक्षणिक वातावरण छात्राओं को उच्च शिक्षा के साथ-साथ शोध की ओर प्रेरित करेगा। इससे विज्ञान, तकनीक, कला और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को भी विस्तार मिलेगा।

4700 दोपहिया वाहनों के साथ 'अभया ब्रिगेड' की शुरुआत

महिला सुरक्षा के लिए 4700 दोपहिया वाहनों के साथ 'अभया ब्रिगेड' अथवा 'पुलिस दीदी' की शुरुआत को भी अभाविप ने महत्वपूर्ण पहल बताया। अभाविप ने कहा कि छात्राओं एवं महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार और समाज दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों और बाजारों के आसपास गश्त किए जाने से विशेषकर छात्राओं में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। ऐसी पहल महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ राज्य में सुरक्षित वातावरण निर्माण की दिशा में सहायक होगी।

शोध छात्रों के लिए भी फेलोशिप की मांग

अभाविप, दक्षिण बिहार प्रांत के प्रांत मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा महिला शिक्षा, शोध और सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए ये निर्णय स्वागतयोग्य हैं। शोध छात्राओं को आर्थिक सहयोग, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 'अभया ब्रिगेड' की शुरुआत से राज्य की बेटियों को आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि शोध छात्रों के लिए भी फेलोशिप की शुरुआत की जानी चाहिए। साथ ही, इन सभी निर्णयों का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि राज्य की अधिक से अधिक छात्राओं एवं शोधार्थियों तक इनका वास्तविक लाभ पहुंच सके। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

निजी विश्वविद्यालयों की वित्तीय पारदर्शिता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश स्वागतयोग्य : अभाविप

निजी विश्वविद्यालयों द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने स्वागत किया है। अभाविप ने कहा कि ऑडिट किए गए खातों, शुल्क संरचना तथा सरकार से प्राप्त विभिन्न लाभों एवं सुविधाओं से संबंधित वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का निर्देश उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अभाविप ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की वित्तीय कार्यप्रणाली और शुल्क संरचना में पारदर्शिता विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के हितों से सीधे जुड़ी हुई है। शुल्क, वित्तीय प्रबंधन तथा सरकार से प्राप्त सुविधाओं एवं लाभों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज के बीच संस्थानों के प्रति विश्वास मजबूत होगा।

अभाविप ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उनके भविष्य को बेहतर दिशा देना होना चाहिए। ऐसे में संस्थानों की वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अभाविप ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश स्वागतयोग्य है। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए यह जानना आवश्यक है कि संस्थान में ली जा रही फीस का स्वरूप क्या है और संस्थान की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार संचालित हो रही है। उच्च शिक्षा केवल एक सेवा या व्यवसाय नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य और समाज के निर्माण से जुड़ा क्षेत्र है। इसलिए विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश से विद्यार्थी हितों की रक्षा और उच्च शिक्षा व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

निजी विश्वविद्यालयों में वित्तीय पारदर्शिता क्यों बनी बड़ा मुद्दा

देश में उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका लगातार बढ़ी है। ऐसे में इन संस्थानों की शुल्क संरचना, आय-व्यय और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता का सवाल विद्यार्थियों, अभिभावकों और व्यापक सार्वजनिक हित से जुड़ गया है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर 2026 के निर्देश में देशभर के निजी विश्वविद्यालयों से पिछले पांच वर्षों के ऑडिट किए गए वित्तीय रिकॉर्ड, शुल्क संरचना, प्राप्त धनराशि के उपयोग, अधिशेष राशि और उसके निवेश का विवरण मांगा है। साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक, प्रवेश प्रक्रिया, शिकायत निवारण व्यवस्था तथा नियामकीय निरीक्षण से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है।

न्यायालय ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित संस्थानों से जानकारी प्राप्त कर छह सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को निर्धारित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निजी विश्वविद्यालयों को लाभ कमाने वाली संस्थाओं के रूप में संचालित नहीं किया जा सकता। हालांकि, संस्थान के संचालन, विकास और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए उचित अधिशेष रखा जा सकता है। ऐसे में वित्तीय पारदर्शिता उच्च शिक्षा में जवाबदेही और विद्यार्थियों के हितों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। ■ *(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)*

शोधार्थियों की लंबित डॉक्टोरल फेलोशिप तत्काल जारी करने की मांग अभाविप ने एनसीईआरटी निदेशक को सौंपा ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के निदेशक प्रा. दिनेश प्रसाद सकलानी को ज्ञापन सौंपकर एनसीईआरटी डॉक्टोरल फेलोशिप के भुगतान में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। अभाविप ने सात माह से लंबित फेलोशिप का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने तथा भविष्य में इसके नियमित एवं समयबद्ध भुगतान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग की है।



अभाविप ने कहा कि एनसीईआरटी डॉक्टोरल फेलोशिप का भुगतान सामान्यतः त्रैमासिक आधार पर किया जाता है, लेकिन अगस्त 2026 तक शोधार्थियों को पिछले सात माह की फेलोशिप प्राप्त नहीं हुई है। फेलोशिप पर निर्भर अनेक शोधार्थियों को इसके लंबे समय से लंबित रहने के कारण अपने शोध, शैक्षणिक गतिविधियों और आवश्यक खर्चों के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रभावित शोधार्थियों ने ईमेल एवं अन्य आधिकारिक माध्यमों से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर फेलोशिप भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने तथा शीघ्र समाधान की मांग की, लेकिन अब तक भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अभाविप ने एनसीईआरटी से लंबित राशि का तत्काल भुगतान करने के साथ ही भविष्य में फेलोशिप के नियमित और समयबद्ध भुगतान के लिए पारदर्शी एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि शोधार्थियों की शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रह सकें।

अभाविप ने कहा कि शोधार्थियों की फेलोशिप में सात माह की देरी अत्यंत गंभीर विषय है। शोधार्थी अपनी शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों के साथ-साथ आवश्यक खर्चों के लिए इस आर्थिक सहायता पर निर्भर रहते हैं। फेलोशिप समय पर न मिलने से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके शोध कार्य की निरंतरता भी प्रभावित होती है।

उन्होंने कहा कि शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे शोधार्थियों को आवश्यक सहयोग समय पर उपलब्ध कराएं। अभाविप ने एनसीईआरटी से मांग की है कि लंबित फेलोशिप का बिना किसी और विलंब के तत्काल भुगतान किया जाए तथा भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शोधार्थियों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और फेलोशिप के भुगतान को लेकर अनिश्चितता में रखना उचित नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनसीईआरटी विषय की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र कार्रवाई करेगा और शोधार्थियों को राहत प्रदान करेगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)



महिला सुरक्षा को लेकर अभाविप का प्रदर्शन
पुलिस एवं विवि प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं के विरोध में दिल्ली पुलिस मुख्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी स्थित कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अभाविप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों एवं विश्वविद्यालय परिसरों के आसपास महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली पुलिस, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन एवं दिल्ली सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल प्रभावी बनाने की मांग की।

पिछले दिनों दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं एवं छात्राओं से जुड़ी कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। कालकाजी स्थित आस्था कुंज पार्क के पास 17 वर्षीय किशोरी से संबंधित यौन अपराध की घटना, मुखर्जी नगर के हकीकत पार्क के पास दिल्ली विश्वविद्यालय की दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़, पीछा करने और आपत्तिजनक टिप्पणियों की घटना, लेडी श्रीराम कॉलेज के पिछले गेट के पास दुष्कर्म की घटना, विजय नगर क्षेत्र में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ताप्ती हॉस्टल के पास छात्रा द्वारा बाहरी व्यक्तियों के अनुचित व्यवहार को लेकर की गई शिकायत ने विश्वविद्यालय परिसरों एवं छात्र बहुल क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता पैदा की है। इसके अतिरिक्त, एक महिला छात्रा कार्यकर्ता के संबंध में यूट्यूबर नकुल धुल द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला भी छात्राओं की गरिमा एवं सुरक्षा के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अभाविप ने प्रदर्शन के पश्चात दिल्ली पुलिस आयुक्त के नाम विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, छात्रावासों, पीजी, कोचिंग सेंटर एवं छात्र बहुल क्षेत्रों की सुरक्षा की नियमित समीक्षा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की विशेष समिति गठित करने, दिल्लीभर के डार्क स्पॉट एवं संवेदनशील स्थानों का सुरक्षा ऑडिट कराने, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट एवं कार्यशील सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की मांग की गई।

अभाविप ने शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, पीजी क्षेत्रों, पार्कों, बाजारों एवं छात्र आवाजाही वाले प्रमुख मार्गों पर विशेषकर शाम और रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, प्रमुख महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के आसपास विशेष

महिला पुलिस सहायता बूथ स्थापित करने तथा रणनीतिक छात्र क्षेत्रों में महिला सुरक्षा प्रतिक्रिया वाहनों एवं पीसीआर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी की। साथ ही, छात्राओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने और गंभीर मामलों में दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई।

अभाविप दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा केवल घटना के बाद कार्रवाई तक सीमित विषय नहीं हो सकती। आवश्यकता ऐसी पुलिस व्यवस्था की है जो अपराध होने से पहले संवेदनशील एवं असुरक्षित स्थानों की पहचान कर प्रभावी निवारक कदम उठाए। छात्राओं को महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्रावास, पीजी, पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार को आपसी समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल मजबूत करना चाहिए।

डूसू अध्यक्ष यश डबास ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली प्रत्येक छात्रा को सुरक्षित वातावरण मिलना उनका अधिकार है। सुरक्षा केवल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार या परिसर तक सीमित नहीं रह सकती। छात्राओं के आने-जाने वाले रास्तों, बैक गेट, आसपास की सड़कों, छात्रावास एवं पीजी क्षेत्रों में भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। हाल की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस एवं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े सभी संवेदनशील क्षेत्रों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराना चाहिए। पिंक पुलिस बूथ, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी निगरानी एवं नियमित पुलिस पेट्रोलिंग जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए तथा छात्राओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अभाविप दिल्ली ने कहा कि महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा के लिए केवल प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के बजाय प्रभावी निवारक एवं सतत सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। संगठन ने संबंधित प्रशासन से सभी मांगों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। प्रतिक्रिया ।

उमर खालिद को 'राष्ट्रवादी' बताकर कांग्रेस ने राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी: अभाविप

कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद द्वारा उमर खालिद को 'राष्ट्रवादी' बताए जाने संबंधी बयान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय मंत्री श्रवण बी. राज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा ऐसे व्यक्तियों को 'राष्ट्रवादी' बताया जाना उसके राष्ट्रवाद की बदलती परिभाषा को दर्शाता है।

श्रवण बी. राज ने कहा कि जो कांग्रेस महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रवादी मानती थी, आज वही उमर खालिद और शरजील इमाम को राष्ट्रवादी बता रही है। यदि कांग्रेस सत्ता में होती तो शरजील इमाम और उमर खालिद को पद्मश्री दे देती। उन्होंने कहा कि अफजल गुरु के समर्थन तथा 'फ्री कश्मीर' जैसे नारों और अभियानों से जुड़े विवादित प्रसंगों के संदर्भ में जिन व्यक्तियों को लेकर सार्वजनिक रूप से प्रश्न उठते रहे हैं, उन्हें 'राष्ट्रवादी' बताना दुर्भाग्यपूर्ण है।

अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध खड़े होने वाले किसी भी तत्व का महिमामंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय और शैक्षणिक परिसर ज्ञान, शोध, तर्कपूर्ण विमर्श तथा स्वस्थ बहस के केंद्र हैं। अभाविप प्रत्येक विषय पर अकादमिक चर्चा और विचार-विमर्श की पक्षधर है, लेकिन अकादमिक स्वतंत्रता की आड़ में आतंकवाद अथवा देशविरोधी गतिविधियों के महिमामंडन और सामान्यीकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी समूहों और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठनों द्वारा ऐसे विषयों को शैक्षणिक परिसरों में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों की स्क्रीनिंग अथवा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से विवादित गतिविधियों और व्यक्तियों को सामान्य विमर्श का हिस्सा बनाने के प्रयासों का अभाविप विरोध करेगी।

श्रवण बी. राज ने कहा कि शैक्षणिक परिसरों में स्वस्थ और तर्कपूर्ण बहस का स्वागत है, लेकिन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के महिमामंडन के लिए विश्वविद्यालयों की गरिमा और अकादमिक वातावरण का उपयोग नहीं होने दिया जा सकता। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

शब्द बने स्वर, कविता बनी चेतना-'अक्षरम्' में मुखर हुआ युवा मन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के तत्वावधान में गत, 12 सितंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मधुबन पार्क में 'अक्षरम्-काव्य प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों में साहित्य एवं काव्य के प्रति अनुराग बढ़ाने, उनकी सृजनात्मक चेतना को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करने तथा युवा मन की संवेदनाओं को शब्द देने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से लगभग 150 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।



प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी मौलिक काव्य-रचनाओं एवं सस्वर काव्य-पाठ के माध्यम से सामाजिक सरोकारों, सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रबोध और समसामयिक विषयों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया। उनकी रचनाओं में कहीं सामाजिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति दिखाई दी, तो कहीं राष्ट्र और संस्कृति के प्रति अनुराग एवं गौरव का भाव उभरकर सामने आया। प्रतिभागियों की रचनात्मकता, भावाभिव्यक्ति और प्रभावशाली प्रस्तुति ने आयोजन को जीवंत बना दिया।

काव्य-रचनाओं का मूल्यांकन निर्णायक मंडल द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया गया। रचनात्मकता, विषय-वस्तु, भाषा-शैली, भावाभिव्यक्ति एवं प्रस्तुति-कौशल के आधार पर श्रेष्ठ प्रस्तुतियों का चयन कर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह ने समापन संबोधन में प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि कविता केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज की चेतना, संवेदना और सांस्कृतिक स्मृति को स्वर देने वाली सशक्त विधा है। कविता व्यक्ति को अपने समय से संवाद करने, प्रश्न उठाने और अपनी अनुभूतियों को सार्थक शब्द देने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को निरंतर परिष्कृत करने, साहित्य का अध्ययन करने तथा समाज और संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने का आह्वान किया।

अभाविप बीएचयू इकाई की छात्रा कार्यकर्ता मेघा मुखर्जी ने अपने वक्तव्य में भारतीय इतिहास की वीरांगनाओं और जौहर की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि जौहर को केवल कायरता की कथा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह उन महिलाओं के साहस और अस्मिता की रक्षा के संकल्प से जुड़ी ऐतिहासिक घटना है, जिन्होंने अपने सम्मान की रक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया। उन्होंने जेएनयू में पूर्व में उठे 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसे नारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अभाविप राष्ट्रीय गरिमा और राष्ट्र की एकता से जुड़े विषयों पर सदैव अपनी आवाज उठाती रही है तथा ऐसे नारों का विरोध करती है।

अभाविप बीएचयू विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष पल्लव सुमन ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी साहित्यिक प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ उनके भीतर छिपे रचनाकार को अभिव्यक्ति का सशक्त मंच प्रदान करती हैं।

कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन अभाविप बिएचयू इकाई मंत्री अनुराग तिवारी ने किया। आयोजन ने 'शब्दों से सृष्टि, भावों से भारती, काव्य से संस्कृति' के भाव को प्रभावी रूप से साकार किया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)



छात्र समस्याओं को लेकर अभाविप का हल्लाबोल कुलपति कार्यालय के घेराव के बाद बनी सहमति

लखनऊ विश्वविद्यालय में लंबे समय से लंबित छात्रहित से जुड़े विभिन्न विषयों के समाधान की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई ने गत 21 सितंबर को कुलपति कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान छात्रावास, मेस, स्वच्छता, पेयजल, पुस्तकालय, साइबर लाइब्रेरी, शोधार्थियों तथा अन्य शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर कुलपति को विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभाविप द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

अभाविप ने छात्रावासों में मेस एवं भोजन की गुणवत्ता में सुधार, स्वच्छता और पेयजल की समुचित व्यवस्था, आवश्यक मरम्मत कार्य तथा पुस्तकालय एवं साइबर लाइब्रेरी में पर्याप्त पुस्तकों, ई-जर्नल्स और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से रखी।

पीएचडी शोधार्थियों के इंस्टीट्यूशनल आईडी, पीएचडी कॉमन रूम, विभागीय पुस्तकालय एवं छात्रावास से जुड़े विषयों के समाधान के लिए कमिटी गठित करने तथा उसमें विद्यार्थियों को भी सदस्य बनाए जाने पर सहमति बनी। प्रशासन की ओर से संबंधित कमिटी यथाशीघ्र निर्णय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही गई।

इसके अतिरिक्त ललित कला संकाय एवं विजुअल आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर लैब, आवश्यक उपकरण तथा अन्य प्रशासनिक समस्याओं के समाधान की मांग भी अभाविप ने रखी।

अभाविप, अवध प्रांत के प्रांत मंत्री अर्पण कुशवाहा ने कहा, कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों ने एकजुट होकर विश्वविद्यालय में छात्रहित से जुड़े विषयों को प्रशासन के समक्ष रखा। वार्ता में हमारी सभी प्रमुख मांगों पर प्रशासन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। अब आवश्यक है कि इन मांगों का निर्धारित समयसीमा में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। अभाविप आगामी दिनों में इन निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करेगी।

अभाविप लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई की उपाध्यक्ष वर्तिका ने कहा कि मेस, स्वच्छता, पेयजल, पुस्तकालय और शोधार्थियों से जुड़े विषय विद्यार्थियों के दैनिक जीवन एवं अध्ययन से सीधे जुड़े हैं। प्रशासन ने इन सभी विषयों के समाधान का आश्वासन दिया है। अभाविप इनके क्रियान्वयन पर निरंतर निगरानी रखेगी। वहीं इकाई मंत्री आर्यन ने कहा कि अभाविप विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रशासन से संवाद करती रही है। वार्ता में विशेष रूप से पीएचडी शोधार्थियों से जुड़े विषयों पर विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जल्द निर्णय प्रस्तुत करने पर सहमति बनी है। मांगों के प्रभावी क्रियान्वयन तक अभाविप अपना संवाद और निगरानी जारी रखेगी। ■ *(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)*

आयुष इंटर्नशिप विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में समान वृद्धि की मांग को लेकर अभाविप ने निकाला मार्च

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, गौरीघाट (जबलपुर) के बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) इंटर्नशिप विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में वृद्धि तथा सभी आयुष इंटर्नशिप विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में एमबीबीएस इंटर्नशिप विद्यार्थियों के समान वृद्धि की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने गत 22 सिंतबर 2026 को मार्च निकाला।



अभाविप के नेतृत्व में 300 से अधिक बीएएमएस इंटर्नशिप विद्यार्थी मार्च में शामिल हुए। मार्च जबलपुर आयुर्वेद महाविद्यालय, गौरीघाट से शुरू होकर झंडा चौक पहुंचा। यहां विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर आयुष इंटर्नशिप विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में व्याप्त अंतर की ओर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्टाइपेंड में समान वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया।

अभाविप के प्रांत मंत्री सुव्रत बाझल ने कहा कि आयुष इंटर्नशिप विद्यार्थी अपनी अनिवार्य इंटर्नशिप के दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की देखभाल से सीधे जुड़े रहते हैं। उनके कार्य घंटे, नैदानिक प्रशिक्षण (क्लिनिकल ट्रेनिंग) और जिम्मेदारियों को देखते हुए आर्थिक असमानता उचित नहीं है। अभाविप की मांग स्पष्ट है-समान कार्य के लिए समान सम्मान और समान स्टाइपेंड वृद्धि। यह मांग केवल बीएएमएस तक सीमित नहीं, बल्कि सभी आयुष विद्यार्थियों के इंटर्नशिप स्टाइपेंड में समान वृद्धि की है।

जिज्ञासा आयाम के प्रांत संयोजक अमित सिंह ने कहा कि शासन को आयुष इंटर्नशिप विद्यार्थियों के स्टाइपेंड की तत्काल समीक्षा कर उसमें वृद्धि करते हुए इसे एमबीबीएस इंटर्नशिप विद्यार्थियों के समान स्तर पर लाने की दिशा में आवश्यक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप केवल औपचारिक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा का महत्वपूर्ण नैदानिक चरण है। इस दौरान विद्यार्थी बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी), आंतरिक रोगी विभाग (आईपीडी), अस्पताल राउंड, मरीजों की देखभाल, क्लिनिकल ट्रेनिंग, जांच एवं उपचार संबंधी गतिविधियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) के आधिकारिक असेसमेंट फ्रेमवर्क में इंटर्नशिप विद्यार्थियों को दिए जाने वाले स्टाइपेंड को संस्थानों के मूल्यांकन के निर्धारित पैरामीटर में शामिल किया गया है।

अभाविप जबलपुर महानगर मंत्री आर्यन पुंज ने कहा कि यदि हमारी मांगें स्वीकार नहीं की गईं, तो हम इस आंदोलन को आगे बड़े स्वरूप में करेंगे और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे। अभाविप विद्यार्थियों की इस मांग को लेकर आगे भी आवाज उठाती रहेगी।

विद्यार्थियों ने कहा कि सभी आयुष पद्धतियों के इंटर्नशिप विद्यार्थी नियमित क्लिनिकल प्रशिक्षण और मरीजों की सेवा से जुड़े रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें एमबीबीएस इंटर्नशिप विद्यार्थियों के समान स्टाइपेंड नहीं मिलना असमानता का विषय है।

जानकारी हो कि बीएएमएस इंटर्नशिप विद्यार्थियों को 9,383 प्रतिमाह, जबकि एमबीबीएस इंटर्नशिप विद्यार्थियों को 21,500 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिल रहा है। विद्यार्थियों ने इस अंतर को समाप्त करते हुए सभी आयुष इंटर्नशिप विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में एमबीबीएस इंटर्नशिप विद्यार्थियों के समान वृद्धि करने तथा भविष्य में भी समय-समय पर समान रूप से वृद्धि किए जाने की मांग की। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर अभाविप ने उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(अभाविप) मध्य भारत प्रांत के प्रतिनिधिमंडल ने 14 सितंबर 2026 को प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार से भेंट कर प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों की बहाली तथा शासकीय महाविद्यालयों की मूलभूत व्यवस्थाओं को तत्काल सुदृढ़ करने की मांग को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। जानकारी हो कि इससे पहले अभाविप द्वारा प्रदेशव्यापी 'विद्यार्थी हुंकार अभियान' का आयोजन किया गया था। अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न विषयों को शासन के समक्ष रखा गया है।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 'विद्यार्थी हुंकार अभियान' प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं और उनके भविष्य से जुड़े विषयों को शासन तक पहुंचाने का व्यापक प्रयास है। अभाविप ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षकों के रिक्त पदों तथा प्रशासनिक स्तर पर विद्यार्थियों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं से उच्च शिक्षा मंत्री को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आवश्यक संसाधनों एवं सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।

अभाविप ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि अनेक महाविद्यालयों में आज भी पठन-पाठन से संबंधित मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं, ग्रंथालयों तथा आधुनिक डिजिटल कक्षाओं का विस्तार किए जाने के साथ ही दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए परिवहन, छात्रावास और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। संगठन ने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने छात्रसंघ चुनावों की बहाली की मांग को भी प्रमुखता से रखते हुए कहा कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। अभाविप के अनुसार, छात्रसंघ चुनावों के माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, प्रशासनिक दक्षता, दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। परिसरों में छात्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति विद्यार्थियों और महाविद्यालय प्रशासन के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करने में भी सहायक हो सकती है, जिससे छात्र समस्याओं को संस्थागत स्तर पर उठाने और उनके समाधान की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है।

अभाविप मध्य भारत प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव परिसरों में सकारात्मक छात्र सहभागिता को बढ़ावा देने के साथ विद्यार्थियों को नेतृत्व एवं जिम्मेदारी का अनुभव प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों, महाविद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं तथा लोकतांत्रिक छात्र सहभागिता से जुड़े इन विषयों पर शासन को गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

वार्ता के अंत में शासन की ओर से प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया कि प्रदेश के युवाओं एवं छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक हितों और उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अभाविप द्वारा प्रस्तुत मांगों एवं प्रस्तावों पर उच्च स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार चरणबद्ध रूप से सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

अभाविप ने निकाला प्रतिरोध मार्च, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

जमुई में छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार के प्रकरण को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। घटना के विरोध में अभाविप कार्यकर्ताओं ने गत 25 सितंबर को जमुई में प्रतिरोध मार्च निकाला। वहीं, अभाविप दक्षिण बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने पटना में अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) के. सुहिता अनुपम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

अभाविप द्वारा आयोजित प्रतिरोध मार्च में बड़ी संख्या में छात्रों एवं युवाओं ने भाग लिया और घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। अभाविप ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच कराने तथा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। अभाविप ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता नहीं होनी चाहिए।

वहीं पटना में अपर पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौपकर छात्रा एवं उसके परिवार की सुरक्षा तथा निजता सुनिश्चित करने, मामले से जुड़े सभी तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों की गंभीरता से जांच करने और जांच में किसी व्यक्ति की संलिप्तता प्रमाणित होने पर उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की गई। अभाविप ने यह भी कहा कि दोष सिद्ध होने की स्थिति में न्यायालय एवं कानून के प्रावधानों के अनुरूप कठोर दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अभाविप दक्षिण बिहार के प्रांत मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि जमुई में छात्रा से जुड़ा प्रकरण अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को विद्यालय, महाविद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों तक आने-जाने के दौरान सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना शासन-प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाने तथा दोष सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने कहा कि बिहार में छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों एवं उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा आवश्यक है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त प्रभावी बनाने, छात्राओं की शिकायतों पर त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई करने तथा महिला सुरक्षा से संबंधित शिकायत एवं सहायता तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रतिनिधिमंडल ने अपर पुलिस महानिदेशक के समक्ष पूरे बिहार में छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से संबंधित विभिन्न मांगें भी रखीं। अभाविप ने कहा कि महिला एवं छात्रा सुरक्षा से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ लेते हुए कानून के अनुरूप त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

सुधी पाठकों!

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' सितंबर-2026 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों एवं खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in

rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti



पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं ने लिया सामूहिक संकल्प

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित विषय नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी है। विशेषकर युवा पीढ़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति जागरूक होकर अपने व्यवहार और जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन लाए तो सतत एवं स्वच्छ समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर विकासार्थ विद्यार्थी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहयोग से मणिपुर की राजधानी इंफाल में स्टेट एनवायरनमेंट कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया।

कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इरोइसेम्बा, इंफाल के सभागार में आयोजित इस राज्यस्तरीय कॉन्क्लेव में मणिपुर के 7 जिलों के 44 परिसरों से 468 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवनशैली तथा पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित था।

कॉन्क्लेव में 'From Conclave to Campus: Inspiring a Sustainable Lifestyle through Environmental Action' तथा 'Eco-Conscious Youth for a Sustainable Manipur: Combating Plastic Pollution' विषयों पर विशेष चर्चा हुई। पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवनशैली, युवाओं की भूमिका, जलवायु के प्रति जिम्मेदारी और प्लास्टिक प्रदूषण जैसी चुनौतियों पर चार सत्र आयोजित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि केवल पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जागरूकता को व्यवहारिक कार्रवाई में

परिवर्तित करना आवश्यक है। इस दिशा में विद्यार्थी और युवा परिवर्तन के प्रभावी वाहक बन सकते हैं।

कॉन्क्लेव के अंतर्गत आयोजित विद्यार्थी सहभाग सत्र आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें 103 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मॉडल मेकिंग, पोस्टर एवं स्लोगन तथा पेंटिंग प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी रचनात्मक सोच और प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त किया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिनव मॉडलों, विचारपूर्ण स्लोगनों और चित्रों ने पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता को प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया। स्टेट एनवायरनमेंट कॉन्क्लेव 3.0 ने पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति विद्यार्थियों और युवाओं में जागरूकता पैदा करने के साथ उन्हें अपने परिसरों और समुदायों में ठोस पर्यावरणीय पहल के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया गया कि स्वच्छ, हरित और सतत मणिपुर का निर्माण केवल नीतियों से नहीं, बल्कि समाज की सक्रिय सहभागिता और जिम्मेदार जीवनशैली से संभव है। 7 जिले, 44 परिसर और 468 प्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ कॉन्क्लेव ने पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए स्वच्छ, हरित और सतत मणिपुर के निर्माण का सामूहिक संकल्प दोहराया।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अधिकारिमायुम शारदा देवी, मणिपुर सरकार के वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक एल. जॉयकुमार सिंह, विकासार्थ विद्यार्थी की राष्ट्रीय संयोजक कुमारी पायल राय, अभाविप के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉ. थियाम डेविड सिंह, विकासार्थ विद्यार्थी मणिपुर की प्रांत प्रमुख डा. अरिबाम इंदिरा, विकासार्थ विद्यार्थी मणिपुर के संयोजक पोतशांगबम बोरिश, मणिपुर सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव आर.के. अमरजीत सिंह, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशक टी. ब्रजकुमार, एनआईटी मणिपुर के कुलसचिव प्रा. खुमुकचम टोम्बा सिंह तथा अभाविप मणिपुर प्रांत के संगठन मंत्री भगवत सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित करे राज्य सरकार: अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने ओडिशा के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संसद चुनाव जल्द कराने और इसकी निर्धारित तारीख तत्काल घोषित करने की मांग की है। अभाविप ने कहा है कि यदि सरकार ने शीघ्र स्पष्ट निर्णय नहीं लिया, तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।

अभाविप की ओडिशा (पूर्व) की प्रदेश मंत्री दीप्तिमयी प्रतिहारी ने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले करीब आठ वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। उनके अनुसार,परिसर को लोकतंत्र की नर्सरी माना जाता है और वहां चुनाव नहीं होने से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता के विकास तथा लोकतांत्रिक भागीदारी के अवसर प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि छात्र समुदाय छात्र संघ चुनाव को लेकर आशान्वित है, लेकिन राज्य सरकार इस मुद्दे पर केवल सकारात्मक संकेत या आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव कब कराया जाएगा और इसकी निश्चित तारीख कब घोषित की जाएगी।

प्रतिहारी ने कहा कि यदि सरकार जल्द इस दिशा में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लेती है, तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अभाविप सरकार की कथित छात्र-विरोधी नीति के खिलाफ व्यापक विरोध दर्ज कराएगी।

अभाविप ने कहा कि कैंपस में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए उसका आंदोलन जारी रहेगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

हमीरपुर में छात्र गर्जना रैली का आयोजन

फीस वृद्धि रोकने, छात्र संघ चुनाव बहाल करने और शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), हिमाचल प्रदेश द्वारा गत 08 सिंतबर को हमीरपुर में राज्यस्तरीय छात्र गर्जना रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रदेशभर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। भीषण गर्मी के बावजूद विद्यार्थियों की भारी उपस्थिति ने छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं की आवाज को मजबूती प्रदान की। गांधी चौक पर आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार से छात्र समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग उठाई।

रैली की मुख्य अतिथि अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री क्षमा शर्मा ने कहा कि हमीरपुर की भीषण गर्मी में सड़कों पर उतरी युवा शक्ति यह दर्शाती है कि हिमाचल का युवा बेहतर भविष्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छे रोजगार के अवसर चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा बदलाव चाहता है और उसकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

अभाविप हिमाचल की प्रदेश मंत्री नैंसी अटल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। शिक्षण संस्थानों में फीस में मनमानी वृद्धि, लंबे समय से छात्रसंघ चुनावों का बंद होना तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी विद्यार्थियों के सामने गंभीर समस्याएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को स्थायी रोजगार के बजाय अस्थायी रोजगार तक सीमित रखा जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार के अवसर चाहिए। उन्होंने सरकार से रोजगार के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की मांग की।

प्रदेश मंत्री नैंसी ने सरकार से फीस वृद्धि पर रोक लगाने, छात्रसंघ चुनाव बहाल करने, शिक्षकों के रिक्त पद भरने तथा शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने तथा हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति, अधिष्ठाता और शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग भी उठाई।

फीस वृद्धि पर जताई नाराजगी

अभाविप कार्यकर्ताओं ने शिक्षण संस्थानों में लगातार हो रही फीस वृद्धि पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि फीस बढ़ने से विद्यार्थियों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अभाविप ने छात्रसंघ चुनाव जल्द बहाल करने तथा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद प्राथमिकता के आधार पर भरने की मांग की, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

अभाविप ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नशे का बढ़ता प्रचलन युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

अभाविप ने कहा है कि हमीरपुर से उठी छात्र गर्जना प्रदेशभर के विद्यार्थियों की आवाज है। विद्यार्थी परिषद बेहतर शिक्षा व्यवस्था और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना संघर्ष आगे भी जारी रखेगी। अभाविप ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों का जल्द समाधान नहीं किया तो प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन तेज किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर चक्का जाम और विधानसभा घेराव जैसे आंदोलन भी किए जाएंगे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

अभाविप हिमाचल द्वारा आयोजित छात्र गर्जना रैली की झलकियां





RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 SEPTEMBER, 2026
DATE OF PUBLISHING: 8 SEPTEMBER, 2026

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26



दिल्ली : छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करते एवं इनसेट में ज्ञापन सौंपते अभाविप कार्यकर्ता



भोपाल : छात्रसंघ चुनाव बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को ज्ञापन सौंपते अभाविप कार्यकर्ता